

मुकदमों का विवरण

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम.

मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड और एक और, ई. टी. सी.

(2009 की सिविल अपील संख्या 8527-8529) अक्टूबर 09, 2023

[संजीव खन्ना और एम. एम. सुंदरेश, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: कैप्टिव जेनरेटिंग प्लांट (सी. जी. पी.) / कैप्टिव उपयोगकर्ता यू/आर के लिए पात्रता मानदंड। 3(1)(क) विद्युत नियम, 2005 की; दूसरे परंतुक यू/आर की व्याख्या। 3(1)(क) नियमों और शब्दों के "व्यक्तियों का संघ"; क्या बिजली उत्पादन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में स्थापित एक कंपनी, आर के दूसरे परंतुक के संदर्भ में, "व्यक्तियों का संघ" है। 3(1)((क) नियम।

विद्युत अधिनियम, 2003-एस. 2(8), 9 - विद्युत नियम, 2005 - आर. 3-व्याख्या- कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट (सी. जी. पी.) और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं द्वारा बिजली का उपयोग- ए. पी. टी. ई. एल. के निर्णयों का समन्वय:

आयोजित किया गया: सी. जी. पी. यू/एस. के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए। 9, आर/डब्ल्यू एस। 2(8) अधिनियम के अनुच्छेद (i) और (ii) से आर तक की आवश्यकताएँ। 3(1)(क) नियमों को संतुष्ट करना होगा- सी. जी. पी. यू/एस. की परिभाषा। 2(8) अधिनियम में इन शब्दों का उपयोग किया गया है, "मुख्य रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिए"- इस अभिव्यक्ति को वैधानिक आधार दिया गया है। 3 नियमों के अनुसार- इसमें दो अलग-अलग आवश्यकताएं शामिल हैं- (i) सी. जी. पी. में कैप्टिव उपयोगकर्ता (ओं) के पास स्वामित्व का कम से कम 26 प्रतिशत होना चाहिए- निचली सीमा या न्यूनतम 26 प्रतिशत स्वामित्व निर्धारित है- स्वामित्व की ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है- दूसरी आवश्यकता न्यूनतम बिजली खपत से संबंधित है- कुल बिजली का 51 प्रतिशत या उससे अधिक उपयोगकर्ता (ओं) द्वारा उपभोग किया जाना चाहिए जो स्वामित्व आवश्यकता को पूरा करता है- खंड (बी) से स्पष्टीकरण 1 तक का प्रावधान। 3 इसमें कहा गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अवहेलना करते हुए किसी सहायक या धारक कंपनी द्वारा उपभोग, जब उनमें से कोई एक बंदी उपयोगकर्ता है, तो बंदी उपयोगकर्ता द्वारा बंदी उपभोग के रूप में भी स्वीकार्य होगा- खंड (बी) से स्पष्टीकरण 1 से आर। 3 राज्य 345

344

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड।

वह बंदी उपयोगकर्ता बिजली का अंतिम उपयोगकर्ता है- बंदी उपयोगकर्ता वास्तविक उपभोक्ता है जो अपने उपयोग के लिए बिजली का उपयोग करता है- आर के लिए पहला प्रावधान। 3(1) (क)

पंजीकृत सहकारी समिति द्वारा स्थापित सी. जी. पी. के मामले में लागू होता है-ऐसे मामलों में, पैराग्राफ (i) और (ii) से आर के तहत आवश्यकताएं।3(1)(क) सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से संतुष्ट माना जाता है-आर का दूसरा परंतुक।3(1)(क) नियम उन मामलों में लागू होते हैं जहां बंदी उपयोगकर्ता "व्यक्तियों का संगठन" है-खंड (ग) स्पष्टीकरण 1 से आर तक।3 यह बताता है कि किसी कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट द्वारा स्थापित उत्पादन केंद्र या बिजली संयंत्र के संबंध में स्वामित्व का अर्थ है मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी पूंजी-अन्य मामलों में, स्वामित्व का अर्थ है उत्पादन केंद्र या बिजली संयंत्र पर स्वामित्व हित और नियंत्रण-"व्यक्ति", जैसा कि यू/एस की अवज्ञा है।2(49) इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निगमित निकाय और व्यक्तियों के संघ या निकाय शामिल हैं, चाहे वे निगमित हों या न हों-कंपनियों और व्यक्तियों के संघ के मामले में स्वामित्व का हस्तांतरण एक सामान्य घटना और व्यवसाय की घटना है-एपीटीईएल के कडोदरा पावर मामले में व्याख्या और तर्क इस बात से सहमत हैं-एक सी. जी. पी. अपने स्वामित्व या अपने स्वामित्व के किसी भी हिस्से के हस्तांतरण के कारण अपनी बंदी स्थिति नहीं खोता है, बशर्ते कि हस्तांतरणकर्ता, यानी एक नया बंदी उपयोगकर्ता, निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का पालन करता हो।3 – देश की अर्थव्यवस्था के लिए बिजली के उत्पादन के महत्वपूर्ण होने से निपटने के लिए, एक संकीर्ण व्याख्या वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर देगी, जिससे तर्कहीन परिणाम मिलेंगे -एस. 2 (8) और एस.9(2) एस के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना।9(1) – एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या में सी. जी. पी. का एक बाद का मालिक शामिल होगा, जो स्पष्टीकरण 1 से आर के खंड (सी) के अनुसार एक मालिक है।3 – हालाँकि, तमिलनाडु बिजली मामले में ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के लिए न्यूनतम स्वामित्व और उपभोग मानदंड केवल वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ही संतुष्ट किए जाने की आवश्यकता है, यानी 31 तारीख को सहमति नहीं है-स्वामित्व की न्यूनतम सीमा, जो 26 प्रतिशत है, को पूरे वर्ष पूरा और संतुष्ट किया जाना है, न कि अकेले वित्तीय वर्ष के अंत में।[पैरा 25,27-29,33,35-37,39]

विद्युत अधिनियम, 2003 -धारा 2 (8)-विद्युत नियम, 2005 -आर. 3 (1) (ए)- अनुरोध करें कि चूंकि एस।2(8) अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, "किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थापित बिजली संयंत्र", बंदी उपयोगकर्ता यू/आर।3(1)(क) वह व्यक्ति होना चाहिए जिसने संयंत्र की स्थापना में भाग लिया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि "स्थापित" में बिजली संयंत्र की स्थापना के बाद शेयरों/स्वामित्व का अधिग्रहण शामिल नहीं है।इसलिए, स्वामित्व के हस्तांतरण के माध्यम से बंदी स्थिति का हस्तांतरण अधिनियम के तहत निषिद्ध है:

346

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

आयोजित किया गया:वाक्यांश, खंड एस में उपयोग किया गया "सेट अप"।2(8) अधिनियम को प्रारंभिक व्यवस्था के संदर्भ में पांडित्यपूर्ण तरीके से नहीं पढ़ा जाना चाहिए-व्यावहारिक वास्तविकता को पहचाना जाना चाहिए और इस व्याख्या के अव्यावहारिक अस्वाभाविक परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए -अधिनियम की धारा 2 (8) को सी. जी. पी. की स्थापना

के बाद स्वामित्व के हस्तांतरण के निषेध को निहित रूप से शामिल करने के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए-इस बार को विशिष्ट रूप से नहीं कहा गया है और इसका उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि विधायिका इसे सरल शब्दों में कह सकती थी-बल्कि, एस में 9(1) उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं, "एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का निर्माण, रखरखाव या संचालन"-इस प्रकार, एक सी. जी. पी. का निर्माण, रखरखाव या संचालन 9(1) अधिनियम को अलग-अलग पढ़ा जा सकता है-यह एस में "निर्माण, रखरखाव या संचालन" के संदर्भ में "या" शब्द के उपयोग से उत्पन्न होता है 9(1) – यह विधायी इरादे के अनुरूप तर्कसंगत और उचित व्याख्या होगी-यह आवश्यक नहीं है कि सी. जी. पी. का रखरखाव और संचालन करने वाले व्यक्ति ने सी. जी. पी. का निर्माण भी किया हो-निर्माण, रखरखाव या संचालन अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है-यह नियमों के नियम 3 में सामने लाया गया है जो बंदी उपयोगकर्ताओं के लिए पात्रता मानदंड को निर्दिष्ट करता है -आर. 3 सी. जी. पी. में बंदी उपयोगकर्ता के स्वामित्व के प्रतिशत और पांचवें वित्तीय वर्ष में बंदी उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग/खपत को संदर्भित करता है।[पैरा 32]

विद्युत अधिनियम, 2003-एस.9(2), 9(1) - "प्रत्येक व्यक्ति ";" एक व्यक्ति एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का निर्माण, रखरखाव या संचालन कर सकता है ":

आयोजित किया गया:एस में 9(2) उपयोग किए गए शब्द हैं "प्रत्येक व्यक्ति, जिसने एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का निर्माण किया है और इस तरह के संयंत्र का रखरखाव और संचालन करता है"- "प्रत्येक व्यक्ति" एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित कर सकता है जो सी. जी. पी. का निर्माण नहीं करते हुए सी. जी. पी. का रखरखाव और संचालन करता है, जिसका अर्थ और व्याख्या एस की भाषा से संबंध प्राप्त करती है 9(1) जिसमें कहा गया है कि "एक व्यक्ति एक कैप्टिव जेनरेटिंग प्लांट का निर्माण, रखरखाव या संचालन कर सकता है"-अस्पष्टता के मामले में, व्याख्या के उद्देश्य और उद्देश्य नियम को लागू करना उपयोगी है-एक व्यावहारिक व्याख्या बेहतर है, ताकि विधायी इरादे को ओवरराइड न किया जा सके-अदालत के लिए यह मान लेना वैध है कि विधायिका वास्तविकता को जानती है और व्यावहारिक कानूनों का समर्थन और अधिनियमन करती है जो व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित और बढ़ावा देती है-कानूनों की व्याख्या।[पैरा 34]

विद्युत अधिनियम, 2003-विद्युत नियम, 2005 -आर. 3-दूसरा परंतुक यू/आर।3(1) (क) "व्यक्तियों का संगठन"-व्याख्या-आनुपातिकता सिद्धांत-एकात्मक योग्यता अनुपात-समझाया गया-कड़ोदरा में तर्क 347

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड।

अधिकार डब्ल्यू. आर. टी. आनुपातिकता आवश्यकता के साथ सहमति व्यक्त की गई, स्पष्टीकरणों और अपीलार्थी की ओर से प्रदान किए गए चित्रों का उल्लेख करके विस्तृत किया गया-मालिकों द्वारा दी गई व्याख्या, "खेल", जो आर. का दुरुपयोग और दुरुपयोग होगा।

3(1)(क) नियमों के अनुसार-खेल के ऐसे उदाहरण हैं जहां सी. जी. पी. का एक प्रतिशत या एक महत्वहीन शेयरधारक असमान रूप से उत्पन्न बिजली का उपयोग नहीं कर सकता है, इस

मामले में उसे समूह बंदी उपयोगकर्ता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और इसलिए, बंदी को अधिनियम के तहत दिए जाने वाले लाभों से वंचित किया जाना चाहिए।

उपयोगकर्ता।[पारस 42,43 और 45]

विद्युत अधिनियम, **2003** -धारा **2 (8)**-कैप्टिव जेनरेटिंग प्लांट्स (सी. जी. पी.) की श्रेणियां-बिजली नियम, **2005**-प्रावधान से आर.**3(1)(क)**-समूह बंदी उपयोगकर्ता जो पंजीकृत सहकारी समितियाँ नहीं हैं, आनुपातिकता के परीक्षण का पालन करने के लिए:

आयोजित किया गया:अधिनियम की धारा 2 (8) सी. जी. पी. की दो श्रेणियों को मान्यता देती है, एकल बंदी उपयोगकर्ता और समूह बंदी उपयोगकर्ता-समूह बंदी उपयोगकर्ता के लिए, केवल दो श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं को मान्यता दी जाती है, अर्थात्, एक सहकारी समिति और व्यक्तियों का संघ-आर.3(1)(क) नियमों के तहत सहकारी समितियों के लिए एक अपवाद पैदा होता है-इसके लिए सहकारी समिति के सदस्यों को केवल सामूहिक रूप से अनुच्छेद (i) और (ii) के तहत निर्दिष्ट न्यूनतम स्वामित्व और बिजली खपत आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है।3(1) (ए) नियमों का-आर का दूसरा परंतुक।3(1)(क), जो व्यक्तियों के संगठन को संदर्भित करता है, ऐसे बंदी उपयोगकर्ताओं को आर के पैराग्राफ (i) और (ii) के तहत निर्दिष्ट न्यूनतम स्वामित्व और बिजली खपत आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है।3(1)(क) नियम-इसके अतिरिक्त, ऐसे कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को सी. जी. पी. द्वारा उत्पन्न बिजली का उपभोग करने की भी आवश्यकता होती है, जो सी. जी. पी. के स्वामित्व में उनके व्यक्तिगत शेयरों के अनुपात में 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी, जो 26 प्रतिशत से कम नहीं होगी-इस प्रकार, नियमों के तहत, सभी समूह कैप्टिव उपयोगकर्ता जो पंजीकृत सहकारी समितियाँ नहीं हैं, उन्हें नियम 3 (1) (ए) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट आनुपातिकता परीक्षण का पालन करना आवश्यक है।3(1)(ए) नियमों का मामला विशिष्ट नहीं है सी-इसे एस के तहत अंतर्निहित व्याख्या के लिए उपसंहार के रूप में माना जाना चाहिए।2(8) अधिनियम का, अर्थात् "मुख्य रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिए"-एस के तहत अधिनियम बनाना।2(8) किसी भी उदाहरण में व्यवहार्य अधिनियम का जहां समूह बंदी उपयोगकर्ता पंजीकृत सहकारी समितियाँ नहीं हैं, आर के दूसरे परंतुक के तहत आनुपातिकता का नियम।3(1) (क) नियमों को एक अनिवार्य शर्त के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

348

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

– आर के लिए दूसरा प्रावधान।3(1)(क) नियमों की धारा को आगे बढ़ाने के लिए है।2(8) अधिनियम से। [पारस 61-63]

विद्युत नियम, **2005**-आर के लिए दूसरा प्रावधान।**3(1)(क)**-सी. जी. पी. के स्वामित्व या हिस्सेदारी में परिवर्तन, आर. के दूसरे परंतुक की प्रयोज्यता।**3(1)(अ):**

आयोजित किया गया:स्वामित्व, हिस्सेदारी या खपत के परिवर्तन के मामले में, नियम 3 (1) (ए) के दूसरे परंतुक के तहत निर्धारित आनुपातिक बिजली खपत आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारित औसत के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए-भारित औसत हिस्सेदारी पद्धति को नियम 3 (1) (ए) के दूसरे परंतुक के संदर्भ में उसके द्वारा खपत की जाने वाली आनुपातिक बिजली की गणना करने के उद्देश्य से वर्ष के लिए विशेष शेयरधारक द्वारा आयोजित औसत हिस्सेदारी लेकर लागू किया जाता है-भारित हिस्सेदारी और बिजली की आनुपातिक खपत यह निर्धारित करने के लिए उचित, न्यायसंगत और सही तरीका है कि क्या नियम 3 (1) (ए) के दूसरे परंतुक की आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।[पैरा 47,48]

विद्युत नियम, **2005** -आर. **3**-बिजली उत्पादन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एस. पी. वी.) के रूप में स्थापित एक कंपनी, यदि आर के दूसरे परंतुक के संदर्भ में "व्यक्तियों का संघ" है।**3(1)(क)** नियम और उसमें निर्दिष्ट आनुपातिकता आवश्यकता को पूरा करना:

आयोजित किया गया:कडोदरा पावर में दिए गए तर्क से सहमति हुई -नियमों का आर. 3 (1) (बी) उदारीकरण करता है, एफ. एल. को व्यवहार्यता और एक विकल्प देता है जब कंपनी के स्वामित्व वाले एक उत्पादन केंद्र, जिसे एस. पी. वी. के रूप में शामिल किया गया है, में कई उत्पादन इकाइयाँ हैं -आर. 3 (1) (बी) आर के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूर्ववत या ओवरराइड नहीं करता है। 3(1)(क) दूसरे परंतुक के साथ पढ़ा जाता है-कंपनियों या निकाय निगमों के एक संघ को आर का पालन करना आवश्यक है।3(1)(क) आर के दूसरे परंतुक के साथ पढ़ें।3(1)(क)-समान रूप से, कंपनियों, निकाय निगमों, या अन्य व्यक्तियों का एक संघ जो एक एस. पी. वी. स्थापित करता है जो सी. जी. पी. का स्वामित्व, रखरखाव और संचालन करता है, को आर. का पालन करना आवश्यक है।3(1)(क) आर के दूसरे परंतुक के साथ पढ़ें।3(1)(क)-इस संबंध में एक एस. पी. वी. कंपनी हो सकती है, लेकिन यह आर के दूसरे परंतुक के संदर्भ में व्यक्तियों का एक संघ भी है।3(1)(क)-इस प्रकार, एस. पी. वी. जो सी. जी. पी. का स्वामित्व, संचालन और रखरखाव करते हैं, आर. के दूसरे परंतुक के संदर्भ में "व्यक्तियों का संघ" हैं।3(1)(क) नियमों के अनुसार-कंपनियों, निगमित निकायों और अन्य व्यक्तियों, जो एक एस. पी. वी. द्वारा स्थापित सी. जी. पी. के शेयरधारक और कैप्टिव उपयोगकर्ता हैं, के लिए 349 की आवश्यकता होती है।

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड।

आर का पालन करें।3(1)(क) नियमों के दूसरे परंतुक के साथ पठित नियमों का।[पारस 51,64,66]

शब्द और वाक्यांश-"व्यक्तियों का संगठन"-बिजली अधिनियम, **2003**-बिजली नियम, **2005**:

आयोजित किया गया:"व्यक्तियों का संघ" अभिव्यक्ति का अर्थ उस विशेष संदर्भ के आधार पर अलग-अलग कानूनों में भिन्न हो सकता है जिसमें उस कानून में व्यक्तियों के संघ का उपयोग किया जाता है-इसकी जांच करने की आवश्यकता है कि क्या व्यक्तियों का ऐसा संघ उक्त कानून के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक सामान्य कार्रवाई कर रहा है-अधिनियम और नियमों के संदर्भ में,

कंपनियों या निकाय निगम एक साथ आ सकते हैं और अधिनियम और नियमों के तहत बंदी उपयोगकर्ता (ओं) बनने के सामान्य लाभ को प्राप्त करने के लिए एक सामान्य उद्देश्य के साथ एक एस. पी. वी. के रूप में एक अन्य कंपनी की स्थापना कर सकते हैं, जिससे बंदी उपयोगकर्ताओं को प्रदान किए गए लाभ जैसे कि क्रॉस सब्सिडी या अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करने से छूट, जैसा कि लागू हो-"व्यक्तियों का संघ" शब्द, को विशिष्ट रूप से अवहेलना नहीं किया गया है।²⁽⁴⁹⁾ अधिनियम का प्रावधान न्यायिक और गैर-न्यायिक दोनों व्यक्तियों को शामिल करने के लिए एक "व्यक्ति" के दायरे का विस्तार करता है।[पारस 55,56,60]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

कडोदरा पावर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम गुजरात विद्युत नियामक
आयोग और एक अन्य 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. टी. ई. एल. 119-अनुमोदित।
एस. ई. एस. ए. स्टरलाइट लिमिटेड बनाम उड़ीसा विद्युत नियामक आयोग
और अन्य (2014) 8 एस. सी. सी. 444:[2014] 13 एससीआर 426-प्रतिष्ठित।
तमिलनाडु बिजली उत्पादक संघ बनाम तमिलनाडु बिजली
नियामक आयोग 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. टी. ई. एल. 19; साई वर्धा पावर
जेनरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम महाराष्ट्र विद्युत नियामक
आयोग 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. टी. ई. एल. 78; छत्तीसगढ़ राज्य बिजली
वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक
आयोग और एन. आर. (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 604; महाराष्ट्र राज्य
विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम जे. एस. डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड और अन्य। (2022) 2
एस. सी. सी. 742; ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य बनाम केंद्रीय बिजली
नियामक आयोग (2009) 15 एस. सी. सी. 570:[2009] 9 एस. सी. आर. 22; रमनलाल
भाईलाल पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य (2008) 5 एस. सी. सी. 449:[2008] 2
350 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.
एससीआर 468; एस. सुंदरम पिल्लई और अन्य बनाम वी. आर. पट्टाबिरमन और अन्य
(1985) 1 एससीसी 591:[1985] 2 एस. सी. आर. 643; मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड और
अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2017 का सी. ए. सं. 18506-18507 -
संदर्भित किया गया।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2009 की सिविल अपील सं. 8527-8529।

2008 के अपील Nos.10,171 और 172 में बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के दिनांक 22.09.2009 के निर्णय और आदेश से।के साथ

2010 की सिविल अपील Nos.1-2,1693-1698,2016 की 12282,1142,1141,4611-4624,4532-4556,2022 की 4571,2022 की सिविल अपील डायरी No.10378,2022 की सिविल अपील Nos.3662,4233 और 8738

रूप:

सुखबीर सिंह, संजय जैन, ए. एस. जी., बसव प्रभु एस. पाटिल, सी. ए. सुंदरम, संजय सेन, जी. उमापति, सी. एस. वैद्यनाथन, एम. जी. रामचंद्रन, साजन पूवय्या, नकुल दीवान, जयंत भूषण, एस. के. रूंगटा, जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता।, मेसर्स डी. एस. के. लीगल, जी. साईकुमार, रवि प्रकाश, समीर मलिक, सुश्री निकिता चौकसे, आकाश लांबा, सुश्री फरहा मलिक, नमन टंडन, चंद्र प्रकाश, सुश्री इशिता जैन, आनंद कुमार श्रीवास्तव, सुधीर नंदराजोग, शिवम सिन्हा, अंकित भंडारी, गीत राजन आहूजा, मातृगुप्त मिश्रा, निपुन दवे, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, सुश्री रोहिणी मूसा, जफर इनायत, आनंद के. गणेशन, प्रमोद दयाल, निकुंज दयाल, सुश्री कृति सोनी, रोहित सिंघा, सुश्री तातिनी बसु, पी. विनोद कुमार, सुश्री श्रद्धा देशमुख, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, रोहित के.

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड।

शिवांकुर शुक्ला, सुश्री अमिता सिंह कल्कल, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री जेसल वाही, एम. वाई. देशमुख, डी. कुमानन, श्रीमती दीपा एस., शेख फखरुद्दीन कालिया, सुश्री रचेता चावला, सुश्री दिव्या सिंह, सुश्री बानो देसवाल, राजीव महेश्वरानंद राय, गुंजन कुमार, पी. श्रीनिवासन, सेंथिल जगदीशन, सजल जैन, सुश्री सोनाक्षी मल्हन, सुश्री इशिता जैन, आनंद कुमार श्रीवास्तव, शिवम सिन्हा, अंकित भंडारी, अनिल कौशिक, अभिषेक मिश्रा, श्रीमती शशि शर्मा, रजत राणा, सुश्री अंजू कौशिक, सुश्री अरुणिमा द्विवेदी, गुरमीत सिंह मकडपस्थित पक्षों के लिए

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्याय

संजीव खन्ना, जे।

यह निर्णय विद्युत अधिनियम, 2003 1 और विद्युत नियम, 2005 2 के नियम 3 के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या करता है, जिन्हें कैप्टिव जेनरेटिंग प्लांट 3 और कैप्टिव यूजर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2. हम कानून के अनुसार कानूनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे, हमारा इरादा पहले कानून के सिद्धांतों को निर्धारित करना और फिर प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सिद्धांतों को लागू करना है।

3. कानूनी प्रश्न का निर्णय करने के लिए, हम बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के दो निर्णयों का उल्लेख करेंगे। ये हैं, कडोदरा पावर प्राइवेट लिमिटेड और

अन्य बनाम गुजरात विद्युत नियामक आयोग और अन्य 5, दिनांकित

22.09.2009, कौन सा निर्णय कई तथ्यों के आधार पर लिया गया था

तमिलनाडु विद्युत उत्पादक संघ बनाम तमिलनाडु विद्युत

1 संक्षेप में, "अधिनियम"।

2 संक्षेप में, "नियम"।

3 संक्षेप में, "सी. जी. पी"।

4 संक्षेप में, "एपीटीईएल"।

5 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. टी. ई. एल. 119; संक्षेप में, "कडोदरा पावर"।

352

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

नियामक आयोग 6, दिनांक 07.06.2021। एपीटीईएल का तीसरा निर्णय

साई वर्धा पावर जेनरेशन लिमिटेड और अन्य में। महाराष्ट्र

विद्युत नियामक आयोग 7 दिनांक 26.11.2021, तमिलनाडु पावर 8 के दृष्टिकोण से काफी हद तक सहमत है। हम निर्णयों में दिए गए कारणों और अपने निष्कर्ष और कानूनी निर्णय के लिए स्पष्टीकरण और आधारों का उल्लेख करेंगे।

4. हम अधिनियम 9 के प्रासंगिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करके शुरू करते हैं: “2. परिभाषा।— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, -x

xx

xx

(8) "कैप्टिव जेनरेटिंग प्लांट" का अर्थ है किसी भी व्यक्ति द्वारा मुख्य रूप से अपने उपयोग के लिए बिजली पैदा करने के लिए स्थापित एक बिजली संयंत्र और इसमें किसी भी सहकारी समिति या व्यक्तियों के संघ द्वारा बिजली पैदा करने के लिए स्थापित एक बिजली संयंत्र शामिल है जो मुख्य रूप से ऐसी सहकारी समिति या संघ के सदस्यों के उपयोग के लिए है।

xx

xx

xx

(49) "व्यक्ति" में कोई भी कंपनी या निकाय निगमित या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल होगा, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति;

xx

xx

xx

9. बंदी पीढ़ी।— (1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक व्यक्ति एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र और समर्पित पारेषण लाइनों का निर्माण, रखरखाव या संचालन कर सकता है:

बशर्ते कि ग्रिड के माध्यम से कैप्टिव उत्पादन संयंत्र से बिजली की आपूर्ति को उसी तरह से विनियमित किया जाएगा जैसे एक उत्पादन कंपनी के उत्पादन केंद्र को किया जाता है:

बशर्ते कि कैप्टिव उत्पादन योजना से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति के लिए इस अधिनियम के तहत किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

6 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. टी. ई. एल. 19; संक्षेप में "तमिलनाडु पावर"। 7 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. टी. ई. एल. 78; संक्षेप में, "साई वर्धा"। 8 शीर्ष टिप्पणी 6.

9 जैसा कि 31.08.2023 तक संशोधित किया गया है।

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। [संजीव खन्ना, जे.] 354

353

इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार लाइसेंसधारी और धारा 42 की उप-धारा (2) के तहत बनाए गए विनियमों के अधीन किसी भी उपभोक्ता के लिए।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का निर्माण किया है और ऐसे संयंत्र का रखरखाव और संचालन करता है, को अपने कैप्टिव उत्पादन संयंत्र से अपने उपयोग के गंतव्य तक बिजली ले जाने के उद्देश्यों के लिए खुली पहुंच का अधिकार होगा:

बशर्ते कि ऐसी खुली पहुंच पर्याप्त पारेषण सुविधा की उपलब्धता के अधीन होगी और पारेषण सुविधा की ऐसी उपलब्धता केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो भी मामला हो:

बशर्ते कि पारेषण सुविधा की उपलब्धता के संबंध में किसी भी विवाद पर उपयुक्त आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा।”

5. हम नियम 10 के नियम 3 को भी पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे, जिसकी व्याख्या निर्णय के लिए महत्वपूर्ण है:

“3. कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट की आवश्यकताएँ।—(1) कोई शक्ति नहीं

संयंत्र अधिनियम की धारा 2 के खंड (8) के साथ पठित धारा 9 के तहत 'कैप्टिव जेनरेटिंग प्लांट' के रूप में अर्हता प्राप्त करेगा जब तक कि -

(क) बिजली संयंत्र के मामले में -

(i) स्वामित्व का कम से कम छत्तीस प्रतिशत कैप्टिव उपयोगकर्ता (ओं) के पास है; और

(ii) ऐसे संयंत्र में उत्पन्न कुल बिजली का कम से कम एक प्रतिशत, जो वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाता है, कैप्टिव उपयोग के लिए खपत किया जाता है:

बशर्ते कि पंजीकृत सहकारी समिति द्वारा स्थापित बिजली संयंत्र के मामले में, उपरोक्त (i) और (ii) पैराग्राफ के तहत उल्लिखित शर्तों को सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से पूरा किया जाएगा:

10 जैसा कि 01.09.2023 तक संशोधित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

बशर्ते कि व्यक्तियों के संघ के मामले में, कैप्टिव उपयोगकर्ता (ओं) के पास कुल मिलाकर संयंत्र के स्वामित्व का कम से कम छब्बीस प्रतिशत हिस्सा होगा और ऐसे कैप्टिव उपयोगकर्ता (ओं) बिजली संयंत्र के स्वामित्व में अपने हिस्से के अनुपात में वार्षिक आधार पर निर्धारित बिजली का कम से कम पचास प्रतिशत उपभोग करेंगे, जो दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ख) ऐसे उत्पादन केंद्र के लिए विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में गठित कंपनी के स्वामित्व वाले उत्पादन केंद्र के मामले में, एक इकाई या ऐसे उत्पादन केंद्र की इकाइयों को कैप्टिव उपयोग के लिए पहचाना जाता है, न कि पूरे उत्पादन केंद्र को, उपरोक्त उपखंड (क) के पैराग्राफ (i) और (ii) में निहित शर्तों को पूरा करता है, जिसमें शामिल हैं -

स्पष्टीकरण।— (1) कैप्टिव उपयोगकर्ताओं द्वारा खपत की जाने वाली आवश्यक बिजली का निर्धारण कैप्टिव उपयोग के लिए ऐसी उत्पादन इकाई या इकाइयों के संदर्भ में किया जाएगा, न कि समग्र रूप से उत्पादन केंद्र के संदर्भ में; और

(2) उत्पादन केंद्र में कैप्टिव उपयोगकर्ता (ओं) द्वारा रखे जाने वाले इक्विटी शेयर उत्पादन इकाई या कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के रूप में पहचानी जाने वाली इकाइयों से संबंधित कंपनी की इक्विटी के अनुपात के छत्तीस प्रतिशत से कम नहीं होंगे।

चित्रण।— 50 मेगावाट की दो इकाइयों ए और बी वाले उत्पादन केंद्र में 50 मेगावाट की एक इकाई ए को कैप्टिव जेनरेटिंग प्लांट के रूप में पहचाना जा सकता है। कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के पास कंपनी में इक्विटी शेयरों का कम से कम तेरह प्रतिशत (50 मेगावाट की इकाई ए के अनुपात में छब्बीस प्रतिशत) होगा और वार्षिक आधार पर निर्धारित इकाई ए में उत्पन्न बिजली का कम से कम एक्यावन प्रतिशत कैप्टिव उपयोगकर्ताओं द्वारा खपत किया जाना है। (2) यह सुनिश्चित करना बंदी उपयोगकर्ताओं का दायित्व होगा कि उपरोक्त उप-नियम (1) के उप-खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित प्रतिशत पर बंदी उपयोगकर्ताओं द्वारा खपत को बनाए रखा जाए और यदि किसी भी वर्ष में बंदी उपयोग के न्यूनतम प्रतिशत का पालन नहीं किया जाता है, तो उत्पन्न पूरी बिजली को ऐसा माना जाएगा जैसे कि यह एक उत्पादक कंपनी द्वारा बिजली की आपूर्ति है।

(3) ऐसे उत्पादन संयंत्रों की कैप्टिव स्थिति, जहां कैप्टिव उत्पादन संयंत्र और इसके कैप्टिव उपयोगकर्ता एक से अधिक 355 में स्थित हैं।

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। [संजीव खन्ना, जे.] 356

केंद्र सरकार के अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा राज्य का सत्यापन किया जाएगा।

स्पष्टीकरण।— (1) इस नियम के उद्देश्य के लिए -

(क) 'वार्षिक आधार' का निर्धारण वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाएगा; (ख) 'कैप्टिव यूजर' का अर्थ कैप्टिव जेनरेटिंग प्लांट में उत्पन्न बिजली का अंतिम उपयोगकर्ता होगा और 'कैप्टिव यूज' शब्द का अर्थ तदनुसार किया जाएगा:

बशर्ते कि कैप्टिव उपयोगकर्ता द्वारा बिजली की खपत या तो सीधे या ऊर्जा भंडारण प्रणाली के माध्यम से हो सकती है:

बशर्ते कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (87) की अवहेलना करने वाली सहायक कंपनी या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (46) की अवहेलना करने वाली धारक कंपनी द्वारा की गई खपत, जो एक कैप्टिव उपयोगकर्ता है, कैप्टिव उपयोगकर्ता द्वारा कैप्टिव उपभोग के रूप में भी स्वीकार्य होगी।

(ग) किसी कंपनी या किसी अन्य निगमित निकाय द्वारा स्थापित उत्पादन केंद्र या बिजली संयंत्र के संबंध में 'स्वामित्व' का अर्थ मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर पूंजी होगा। अन्य मामलों में स्वामित्व का अर्थ होगा उत्पादन केंद्र या बिजली संयंत्र पर स्वामित्व हित और नियंत्रण।

(घ) 'विशेष प्रयोजन वाहन' का अर्थ होगा एक कानूनी इकाई जो एक उत्पादन केंद्र का मालिक है, संचालन और रखरखाव करती है और जिसमें कानूनी इकाई द्वारा कोई अन्य व्यवसाय या गतिविधि नहीं की जाती है।”

6. अधिनियम की धारा 2 (8) किसी भी व्यक्ति द्वारा मुख्य रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए स्थापित एक बिजली संयंत्र के रूप में "कैप्टिव जेनरेटिंग प्लांट" को परिभाषित करती है। मुख्य रूप से सहकारी समिति या संघ के सदस्यों के उपयोग के लिए बिजली पैदा करने के लिए सहकारी समिति या व्यक्तियों के संघों द्वारा स्थापित एक बिजली संयंत्र भी एक सी. जी. पी. है।

7. धारा 2 (8) इन शब्दों पर जोर देती है, "मुख्य रूप से अपने लिए।

"और" मुख्य रूप से सहकारी समिति के सदस्यों के उपयोग के लिए

या व्यक्तियों का संगठन "। दूसरा, विशेष रूप से एक सह का उल्लेख करते हुए -

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

ऑपरेटिव सोसाइटी और व्यक्तियों के संघ, खंड किसी कंपनी को संदर्भित नहीं करता है। धारा 2 (49) "व्यक्ति" शब्द को किसी भी कंपनी या निकाय निगमित या संघ या व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति को शामिल करने के लिए परिभाषित करती है।

8. अधिनियम की धारा 2 (8) और धारा 2 (49) को एक साथ पढ़ने पर, एक सी. जी. पी. एक व्यक्ति, निकाय निगमित, संघ या व्यक्तियों का निकाय हो सकता है, चाहे वह निगमित हो या न हो, "मुख्य रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिए" और "मुख्य रूप से इसके लिए"।

सहकारी समिति या व्यक्तियों के संघ के सदस्यों का उपयोग।

निगमित निकायों के एक संघ को सी. जी. पी. स्थापित करने की अनुमति है। 9. अधिनियम की धारा 9, बंदी पीढ़ी से संबंधित एक विशिष्ट प्रावधान, अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान में निहित कुछ भी होने के बावजूद लागू होती है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सी. जी. पी. और समर्पित पारेषण लाइनों का निर्माण, रखरखाव या संचालन कर सकता है। धारा 9 (1) के दूसरे प्रावधान में कहा गया है कि अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी भी लाइसेंसधारी को सी. जी. पी. से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति के लिए अधिनियम के तहत किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, किसी भी उपभोक्ता को आपूर्ति अधिनियम की धारा 42 (2) के तहत बनाए गए नियमों के अधीन है। धारा 9 के पहले प्रावधान में कहा गया है कि ग्रिड के

माध्यम से सी. जी. पी. से बिजली की आपूर्ति को उसी तरह से विनियमित किया जाएगा जैसे एक उत्पादन कंपनी के उत्पादन केंद्र को किया जाता है।

10. अधिनियम की धारा 9 (2) में कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसने सी. जी. पी. का निर्माण किया है और सी. जी. पी. का रखरखाव और संचालन करता है, उसे अपने सी. जी. पी. से अपने उपयोग के गंतव्य तक बिजली ले जाने के उद्देश्य से खुली पहुंच का अधिकार होगा। धारा 9 (2) के पहले प्रावधान में कहा गया है कि ऐसी खुली पहुंच पर्याप्त पारेषण सुविधा की उपलब्धता के अधीन होगी और पारेषण सुविधा की ऐसी उपलब्धता केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा निर्धारित की जाएगी, जैसा भी मामला हो। पारेषण सुविधा की उपलब्धता के संबंध में किसी भी विवाद का निर्णय उपयुक्त आयोग द्वारा किया जाना है।

11. इसलिए, अधिनियम की धारा 9 (2) के संदर्भ में, एक व्यक्ति जिसने एक सी. जी. पी. का निर्माण किया है, और ऐसे संयंत्र का रखरखाव और संचालन करता है, 11

11 जैसा कि अधिनियम की धारा 9 (2) में 'और' शब्द के नीचे समझाया और स्पष्ट किया गया है, जब धारा 9 (1) के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाता है और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या पर एक बाद का मालिक शामिल होता है जो एक सी. जी. पी. का रखरखाव और संचालन करता है। 357 के अनुसार बंदी पीढ़ी

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। [संजीव खन्ना, जे.] 358

उपलब्धता की कमी, वितरण लाइसेंसधारक को अपने सी. जी. पी. से अपने उपयोग के गंतव्य तक बिजली ले जाने के उद्देश्य से पहुँच खोलने के लिए कह सकते हैं। धारा 9 (2) के तहत संचरण सुविधाओं तक पहुँच खोलने का यह अधिकार, धारा 9 (1) में निर्दिष्ट अधिकार के विपरीत होना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सी. जी. पी. का निर्माण, रखरखाव या संचालन कर सकता है और स्व-उपयोग के लिए समर्पित संचरण लाइनों का उपयोग कर सकता है।

12. धारा 9 (1) के संदर्भ में ध्यान देने योग्य तीसरा पहलू यह है कि दूसरा परंतुक एक ऐसे व्यक्ति को अनुमति देता है जिसने सी. जी. पी. का निर्माण, रखरखाव या संचालन किया है, वह सी. जी. पी. से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति किसी भी लाइसेंसधारी को कर सकता है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह आपूर्ति अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन है। इस प्रकार, एक बंदी उपयोगकर्ता के अलावा किसी भी उपभोक्ता को आपूर्ति, अधिनियम की धारा 42 (2) के तहत बनाए गए नियमों के अधीन है। समान रूप से, पहला प्रावधान ग्रिड के माध्यम से सी. जी. पी. से बिजली की आपूर्ति की अनुमति देता है, इस मामले में आपूर्ति को उसी तरह से विनियमित किया जाना है जैसे एक उत्पादन कंपनी के उत्पादन केंद्र में किया जाता है।

13. अतः अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के साथ पठित धारा 9 तीन स्थितियों को अभिनिर्धारित करती है। पहला, जब वह व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सी. जी. पी. का निर्माण, रखरखाव या संचालन करता है और समर्पित पारेषण लाइनों के माध्यम से खुद को बिजली की आपूर्ति करता है। दूसरा, जब वह व्यक्ति जो अपने सी. जी. पी. से अपने उपयोग के गंतव्य तक बिजली ले जाने के

उद्देश्य से खुली पहुंच के अपने अधिकार का प्रयोग करके बिजली की आपूर्ति के लिए सी. जी. पी. का निर्माण, रखरखाव या संचालन करता है। तीसरा, जब सी. जी. पी. से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति किसी भी लाइसेंसधारी या उपभोक्ता के लिए ग्रिड के माध्यम से की जाती है। जबकि किसी लाइसेंसधारी या उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, आपूर्ति अधिनियम की धारा 42 (2) के तहत बनाए गए नियमों के अधीन है।

14. अधिनियम की धारा 42 (1) में कहा गया है कि एक वितरण लाइसेंसधारी का कर्तव्य है कि वह एक प्रभाव, समन्वित और किफायती विकास और रखरखाव करे।

धारा 9 उस व्यक्ति तक सीमित नहीं है जो सी. जी. पी. का निर्माण, रखरखाव और संचालन करता है। यह प्रावधान उस व्यक्ति द्वारा स्वामित्व अधिकारों के हस्तांतरण को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित नहीं करता है जिसने मूल रूप से सी. जी. पी. का निर्माण किया है या स्थापित किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

उसकी आपूर्ति के क्षेत्र में वितरण प्रणाली।¹² एक वितरण लाइसेंसधारी को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिजली की आपूर्ति करने का कर्तव्य भी है। धारा 42 (2) में कहा गया है कि राज्य आयोग द्वारा ऐसे चरणों में खुली पहुंच शुरू की जाएगी, और ऐसी शर्तों के अधीन होगी, जिसमें क्रॉस सब्सिडी और अन्य परिचालन बाधाएं शामिल हैं।¹³ उप-धारा राज्य आयोग को क्रमिक चरणों में खुली पहुंच की सीमा निर्दिष्ट करने और पहियों के लिए शुल्क निर्धारित करने की अनुमति देती है, जो शुल्क क्रॉस सब्सिडी और अन्य परिचालन बाधाओं सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाने हैं।¹⁴ प्रथम परंतुक में कहा गया है कि राज्य आयोग द्वारा निर्धारित व्हीलिंग शुल्क के अलावा अधिभार के भुगतान पर खुले प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।¹⁵ इस तरह के अधिभार का उपयोग, दूसरे परंतुक के संदर्भ में, वितरण लाइसेंसधारी की आपूर्ति के क्षेत्र के भीतर क्रॉस सब्सिडी के वर्तमान स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाना है।¹⁶ तीसरे परंतुक में प्रावधान किया गया है कि क्रॉस सब्सिडी और अधिभार को राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट तरीके से धीरे-धीरे कम किया जाएगा।¹⁷ हमारे विचार के लिए जो महत्वपूर्ण है वह चौथा परंतुक है जिसमें कहा गया है कि

12 “ धारा 42।(वितरण लाइसेंसधारी के कर्तव्य और खुली पहुंच):---(1) यह होगा।

वितरण अनुज्ञप्तिधारी का कर्तव्य अपने आपूर्ति क्षेत्र में एक प्रभावी, समन्वित और किफायती वितरण प्रणाली का विकास और रखरखाव करना और इस अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार बिजली की आपूर्ति करना है।

13 “42(2) राज्य आयोग ऐसे चरणों में और ऐसी शर्तों के अधीन, (क्रॉस सब्सिडी और अन्य परिचालन बाधाओं सहित) ओपन एक्सेस शुरू करेगा, जो उसके द्वारा निर्धारित तिथि के एक वर्ष के भीतर निर्दिष्ट किया जा सकता है और लगातार चरणों में ओपन एक्सेस की सीमा को निर्दिष्ट करने और व्हीलिंग के लिए शुल्क निर्धारित करने में, उसे ऐसी क्रॉस-सब्सिडी और अन्य परिचालन बाधाओं सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखना होगा:”

14 सुप्रा नोट 11.

15 “ धारा 42।(वितरण लाइसेंसधारी के कर्तव्य और खुली पहुंच):---

xx

xx

xx

बशर्ते कि राज्य आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पहियों के शुल्क के अलावा 12 [अधिभार के भुगतान पर ऐसी खुली पहुंच की अनुमति दी जाएगी]:”

16 “ धारा 42।(वितरण लाइसेंसधारी के कर्तव्य और खुली पहुंच):---

xx

xx

xx

बशर्ते कि इस तरह के अधिभार का उपयोग वितरण लाइसेंसधारी की आपूर्ति के क्षेत्र के भीतर क्रॉस-सब्सिडी के वर्तमान स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा:”

17 “ धारा 42।(वितरण लाइसेंसधारी के कर्तव्य और खुली पहुंच):---

xx

xx

xx

“बशर्ते कि ऐसे अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी को राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से उत्तरोत्तर कम किया जाएगा:”

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। [संजीव खन्ना, जे.]
360

359

अपने उपयोग के गंतव्य तक बिजली ले जाने के लिए सी. जी. पी. स्थापित करने वाले व्यक्ति को खुली पहुंच प्रदान किए जाने की स्थिति में अधिभार नहीं लगाया जाएगा। चौथा परंतुक इस प्रकार है:

“42. वितरण लाइसेंसधारी के कर्तव्य और खुली पहुंच।—

xx

xx

xx

बशर्ते कि ऐसा अधिभार उस स्थिति में भी नहीं लगाया जाएगा जब किसी ऐसे व्यक्ति को खुली पहुंच प्रदान की जाती है जिसने अपने उपयोग के गंतव्य तक बिजली ले जाने के लिए एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है:” हमारी राय में, चौथा परंतुक हमारे द्वारा ऊपर विस्तृत की गई दूसरी स्थिति से संबंधित है, अर्थात्, जब वह व्यक्ति जिसने सी. जी. पी. की स्थापना की है, वह

अधिनियम की धारा 9 (2) के संदर्भ में सी. जी. पी. से अपने उपयोग के गंतव्य तक बिजली ले जाने के उद्देश्य से अपने अधिकार का आह्वान करता है। ऐसे मामलों में, कोई अधिभार नहीं लगाया जाता है, भले ही ओपन एक्सेस का अधिकार लागू किया गया हो। हालांकि, वितरण लाइसेंसधारी को अपने उपयोग के गंतव्य तक बिजली की आपूर्ति करने के लिए अपनी वितरण प्रणाली के उपयोग के लिए व्हीलिंग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

15. अधिनियम की धारा 9 और धारा 42 की उपरोक्त व्याख्या, छत्तीसगढ़ राज्य में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार का सम्मानपूर्वक अनुसरण करती है।

विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग और ए. एन. आर. 18 और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम जे. एस. डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड और अन्य। 19.

16. महाराष्ट्र राज्य बिजली 20 में, विशिष्ट सी प्रश्न का उत्तर दिया गया था कि क्या बंदी उपभोक्ता अधिनियम के तहत देय अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। नकारात्मक उत्तर में कहा गया है कि अतिरिक्त अधिभार लगाना अधिनियम 21 की धारा 2 (15) के अनुसार "उपभोक्ता" की अवज्ञा के साथ पठित अधिनियम की धारा 42 (2) के विपरीत होगा, जिसका अर्थ है

18 (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 604; संक्षेप में, "छत्तीसगढ़ राज्य शक्ति"। 19 (2022) 2 एस. सी. सी. 742; संक्षेप में, "महाराष्ट्र राज्य विद्युत"। 20 सुप्रा नोट 19.

21 2. परिभाषा।—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, -×

××

××

(15) "उपभोक्ता" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अपने उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति किसी लाइसेंसधारी या सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है जो

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

एक व्यक्ति जिसे लाइसेंसधारी या सरकार या जनता को बिजली की आपूर्ति करने के व्यवसाय में लगे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाती है और इसमें एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसका परिसर बिजली प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी लाइसेंसधारी, सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति के कार्यों से जुड़ा हुआ है, जैसा भी मामला हो। धाराओं की भाषा के अलावा, इस न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बंदी उपभोक्ता सी. जी. पी. के निर्माण, रखरखाव और संचालन के उद्देश्य से और कभी-कभी समर्पित पारेषण लाइनों पर भारी खर्च करते हैं या पर्याप्त राशि का निवेश करते हैं। इस प्रकार, बंदी उपभोक्ता धारा 2 (15) के तहत एक अलग वर्ग बनाते हैं, जिसका अर्थ है "उपभोक्ता"। 22 वे अधीन नहीं हैं और अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

17. छत्तीसगढ़ राज्य बिजली 23 में, राष्ट्रीय बिजली नीति, 2005 का संदर्भ दिया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा 12.02.2005 पर अधिनियम की धारा 3 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया था। कैप्टिव पीढ़ी और उपयोग से संबंधित नीति के खंड 5.2.24 से 5.2.26 प्रासंगिक हैं, और पढ़ते हैं:

“बंदी पीढ़ी

5.2.24 कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 में उदार प्रावधान न केवल विश्वसनीय, गुणवत्ता और लागत प्रभावी ऊर्जा को सुरक्षित करने के लिए किया गया है, बल्कि उद्योग के त्वरित और प्रभावी विकास के माध्यम से रोजगार के अवसरों के सृजन को भी सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है।

5.2.25 उपभोक्ताओं के समूह द्वारा स्थापित किए जाने वाले कैप्टिव बिजली संयंत्रों से संबंधित प्रावधान का मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों या अन्य उपभोक्ताओं को सक्षम बनाना है जो व्यक्तिगत रूप से लागत प्रभावी तरीके से इष्टतम आकार के संयंत्र स्थापित करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि देश भर में लघु और मध्यम उद्योगों के प्रभावी विस्तार से रोजगार के विशाल अवसर पैदा होंगे।

इस अधिनियम या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत जनता को बिजली की आपूर्ति करना और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसका परिसर बिजली प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी लाइसेंसधारी, सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति के कार्यों से जुड़ा हुआ है।

22 सुप्रा नोट 21.

23 सुप्रा नोट 18.

24 संक्षेप में, "नीति"।

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। [संजीव खन्ना, जे.]
362

361

5.2.26 भारत में बड़ी संख्या में कैप्टिव और स्टैंडबाय उत्पादन स्टेशनों की अधिशेष क्षमता है जिसकी आपूर्ति ग्रिड को लगातार या निश्चित समय अवधि के दौरान की जा सकती है। इन संयंत्रों में एक बड़ी और संभावित प्रतिस्पर्धी क्षमता है जिसका उपयोग बिजली की मांग को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। अधिनियम के तहत, कैप्टिव जनरेटरों के पास लाइसेंसधारियों तक पहुंच है और वे उन उपभोक्ताओं तक पहुंच प्राप्त करेंगे जिन्हें खुली पहुंच की अनुमति है। कैप्टिव जनरेटरों के लिए ग्रिड इंटर-कनेक्शन को अधिनियम की धारा 30 के अनुसार सुविधा प्रदान की जाएगी। यह प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि कैप्टिव उत्पादन ग्रिड के साथ वितरित उत्पादन के रूप में उपलब्ध हो सके। इसके लिए सह-उत्पादन सहित गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी एक भूमिका निभा सकते हैं। कैप्टिव बिजली संयंत्रों से अतिरिक्त क्षमता वाली ऊर्जा का उपयोग करने के लिए लाइसेंसधारियों और कैप्टिव जनरेटरों के बीच उपयुक्त वाणिज्यिक व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता होगी। उपयुक्त विनियामक आयोग कैप्टिव जनरेटरों और लाइसेंसधारियों के

बीच ऐसी वाणिज्यिक व्यवस्थाओं पर नियामक निरीक्षण करेगा और टैरिफ निर्धारित करेगा जब कोई लाइसेंसधारी कैप्टिव संयंत्र से बिजली का ऑफ-टेकर हो।”

18. छत्तीसगढ़ राज्य शक्ति 25 में इस न्यायालय का मानना है कि

अधिनियम के प्रावधान जो कैप्टिव उत्पादन और उपयोग से संबंधित हैं, न केवल विश्वसनीय, गुणवत्ता और लागत प्रभावी सक्रिय शक्ति को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, बल्कि उद्योग के त्वरित और प्रभावी विकास के माध्यम से रोजगार के अवसरों के सृजन को सम्मानित करने के लिए भी बनाए गए हैं। नीति में कहा गया है कि सी. जी. पी. से संबंधित प्रावधान, जिन्हें उपभोक्ताओं के एक समूह द्वारा स्थापित किया जा सकता है, मुख्य रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों और अन्य उपभोक्ताओं को सक्षम बनाने के लिए बनाए गए हैं, जो व्यक्तिगत रूप से लागत प्रभावी तरीके से इष्टतम आकार का बिजली संयंत्र स्थापित करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। देश भर में लघु और मध्यम उद्योगों के प्रभावी विस्तार और विकास से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। अंत में, भारत में कैप्टिव और स्टैंडबाय उत्पादन केंद्र लगातार या निश्चित समय अवधि के दौरान बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी की गई नीति में वैधानिक प्रावधान शामिल हैं। अस्पष्टता के मामले में, एक ऐसी व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो नीति में रेखांकित और बताए गए अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाती है।

25 सुप्रा नोट 18.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

19. इस स्तर पर, हमें इस न्यायालय के पहले के फैसले में अंतर करना चाहिए।

एस. ई. एस. ए. स्टरलाइट लिमिटेड बनाम उड़ीसा विद्युत नियामक आयोग

और अन्य।²⁶ इस मामले में अपीलकर्ता उद्योग ने विशेष आर्थिक क्षेत्र 27 में एक इकाई स्थापित की थी और वह एस. ई. जेड. का विकासकर्ता था। अपीलकर्ता-उद्योग ने एक तीसरे पक्ष के साथ बिजली खरीद समझौता किया था। अपीलकर्ता उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया था कि वह वितरण लाइसेंसधारी से कोई बिजली नहीं ले रहा था या उसका उपयोग नहीं कर रहा था और इसलिए, वह वितरण लाइसेंसधारी का उपभोक्ता नहीं है, और तदनुसार क्रॉस-सब्सिडी अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह एक बंदी उपयोगकर्ता का मामला नहीं था। अपीलार्थी-उद्योग के तर्क को इस न्यायालय द्वारा क्रॉस-सब्सिडी अधिभार के पीछे के तर्क का उल्लेख करते हुए खारिज कर दिया गया था। जो थोक उपभोक्ता खुली पहुंच का लाभ उठाते हैं, उन पर अपेक्षाकृत उच्च दरों का बोझ होता है, क्योंकि इससे समाज के हाशिए पर पड़े और कमजोर वर्गों को बिजली की आपूर्ति पर सब्सिडी मिलती है। इस प्रकार, उपभोक्ताओं के बाहर निकलने से मौजूदा वितरण लाइसेंसधारी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्रॉस सब्सिडी अधिभार का उद्देश्य मौजूदा वितरण लाइसेंसधारी को दो गुना तरीके से क्षतिपूर्ति करना है: पहला, क्रॉस-सब्सिडी के वर्तमान स्तरों की

आवश्यकताओं की भरपाई करना, और दूसरा, मांग पर उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति करने के अपने दायित्व के एक हिस्से के रूप में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा की गई लागत की भरपाई करना, जिसे कभी-कभी फंसे हुए लागत के रूप में संदर्भित किया जाता है। क्रॉस सब्सिडी और अधिभार दोनों मामलों में वितरण लाइसेंसधारी को क्षतिपूर्ति करने के लिए होते हैं। इस प्रकार, यह निर्णय हमारे सामने विचाराधीन कानूनी मुद्दे से संबंधित नहीं है जो सी. जी. पी. की अवज्ञा और बंदी उपयोगकर्ताओं द्वारा बिजली के उपयोग से संबंधित है।²⁰ छत्तीसगढ़ राज्य बिजली 28 और महाराष्ट्र राज्य बिजली 29 में दिए गए कारणों के अलावा, हम अधिनियम 30 की धारा 38 का भी उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें निर्धारित किया गया है कि केंद्र सरकार अधिसूचित कर सकती है।

26 (2014) 8 एस. सी. सी. 444; संक्षेप में, "एस. ई. एस. ए. स्टर्लाइट"।²⁷ संक्षेप में, "एसईजेड"।

28 सुप्रा नोट 18.

29 सुप्रा नोट 19.

30 "38. केंद्रीय पारेषण उपयोगिता और कार्य।—(1) केंद्र सरकार

किसी सरकारी कंपनी को केंद्रीय पारेषण उपयोगिता के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं:

बशर्ते कि केंद्रीय पारेषण उपयोगिता बिजली उत्पादन या बिजली के व्यापार के व्यवसाय में संलग्न नहीं होगी:

बशर्ते कि केंद्र सरकार ऐसी केंद्रीय पारेषण उपयोगिता की बिजली के संचरण में शामिल किसी भी संपत्ति, संपत्ति में ब्याज, अधिकारों और देनदारियों और कर्मियों को किसी कंपनी या 363 को हस्तांतरित और निहित कर सकती है।

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। [संजीव खन्ना, जे.] 364

केंद्रीय पारेषण उपयोगिता के रूप में कोई भी सरकारी कंपनी 31.सी. टी. यू. बिजली उत्पादन और व्यापार के व्यवसाय में संलग्न नहीं हो सकता है। धारा 38 (2) के तहत इसके कार्यों में अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली से संबंधित योजना और समन्वय और उत्पादन स्टेशनों से लोड सेंटर तक बिजली के सुचारु प्रवाह के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण लाइनों की प्रभावी, समन्वित और किफायती प्रणाली का विकास और पारेषण शुल्क के भुगतान पर एक लाइसेंसधारी या उत्पादन करने वाली कंपनी द्वारा उपयोग के लिए इसकी पारेषण प्रणाली तक गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच प्रदान करना और किसी भी उपभोक्ता द्वारा जब भी खुली पहुंच हो, शामिल है।

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत निगमित की जाने वाली कंपनियां, भाग XIII के तहत निर्दिष्ट तरीके से लागू की जाने वाली हस्तांतरण योजना के माध्यम से पारेषण लाइसेंसधारी के रूप में कार्य करेंगी और ऐसी कंपनी या कंपनियों को इस अधिनियम के तहत पारेषण लाइसेंसधारी माना जाएगा।

(2) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता के कार्य होंगे -

(क) अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के माध्यम से बिजली का पारेषण करना; (ख) अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली से संबंधित योजना और समन्वय के सभी कार्यों का निर्वहन करना -

(i) राज्य पारेषण उपयोगिताएँ;

(ख) केंद्र सरकार;

(ग) राज्य सरकारें;

(iv) उत्पादन करने वाली कंपनियाँ;

(v) क्षेत्रीय शक्ति समितियाँ;

(vi) प्राधिकरण;

(vii) लाइसेंसधारी;

(viii) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति;

(ग) उत्पादन स्टेशनों से भार केंद्रों तक बिजली के सुचारु प्रवाह के लिए अंतर-राज्य पारेषण लाइनों की एक प्रभावी, समन्वित और किफायती प्रणाली का विकास सुनिश्चित करना;

(घ) अपनी पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच प्रदान करना-(i) किसी भी लाइसेंसधारी या पारेषण शुल्क के भुगतान पर उत्पादन करने वाली कंपनी; या (ii) किसी भी उपभोक्ता को जब भी धारा 42 की उप-धारा (2) के तहत राज्य आयोग द्वारा पारेषण शुल्क और उस पर अधिभार के भुगतान पर ऐसी खुली पहुंच प्रदान की जाती है, जो केंद्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है:

बशर्ते कि इस तरह के अधिभार का उपयोग वर्तमान स्तर की क्रॉस-सब्सिडी की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाएगा:

बशर्ते कि इस तरह के अधिभार और क्रॉस सब्सिडी को केंद्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट तरीके से धीरे-धीरे कम किया जाएगा:

बशर्ते कि अधिभार के भुगतान और उपयोग का तरीका केंद्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा:

बशर्ते कि ऐसा अधिभार उस स्थिति में भी नहीं लगाया जाएगा जब किसी ऐसे व्यक्ति को खुली पहुंच प्रदान की जाती है जिसने अपने उपयोग के गंतव्य तक बिजली ले जाने के लिए एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।”

31 संक्षेप में, "सीटीयू"।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

धारा 42 (2) के तहत राज्य आयोग द्वारा संचरण शुल्क या उस पर अधिभार के भुगतान पर उपबंध। धारा 38 (2) का चौथा परंतुक इस प्रकार है:

“38. केंद्रीय पारेषण उपयोगिता और कार्य।—

xx

xx

xx

बशर्ते कि ऐसा अधिभार उस स्थिति में भी नहीं लगाया जाएगा जब किसी ऐसे व्यक्ति को खुली पहुंच प्रदान की जाती है जिसने अपने उपयोग के गंतव्य तक बिजली ले जाने के लिए एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।” इस प्रकार, अधिनियम अधिभार, क्रॉस या अतिरिक्त अधिभार

लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, तब भी जब किसी ऐसे व्यक्ति को खुली पहुंच प्रदान की जाती है जिसने अपने उपयोग के गंतव्य तक बिजली ले जाने के लिए सी. जी. पी. स्थापित किया है।

21. यह हमें मुख्य मुद्दे पर लाता है जो नियमों के नियम 3 की व्याख्या से संबंधित है। ए. पी. टी. ई. एल. के मिश्रित निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हमारे विशेष विचार के लिए तीन मुद्दे उत्पन्न होते हैं। ये हैं:

I. नियमों के नियम 3 (1) (ए) के तहत सी. जी. पी./कैप्टिव उपयोगकर्ता के लिए पात्रता मानदंड।

II. नियमों के नियम 3 (1) (ए) के तहत दूसरे प्रावधान की व्याख्या और विशेष रूप से "व्यक्तियों का संगठन" शब्द। III. क्या बिजली उत्पादन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन 32 के रूप में स्थापित कंपनी नियमों के नियम 3 (1) (ए) के दूसरे परंतुक के संदर्भ में "व्यक्तियों का संगठन" है।

नियम **3 (1) (ए)** के तहत निर्दिष्ट सी. जी. पी./कैप्टिव उपयोगकर्ता के लिए मुद्दा I पात्रता मानदंड।

22. नियमों के नियम 3 (1) (ए) की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य शक्ति 33 में की गई थी। उक्त मामले में, मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड। 34 ने सी. जी. पी. की स्थापना की थी। एस. बी. पी. आई. एल. ने पारेषण के माध्यम से बिजली के पहिये के लिए खुली पहुंच प्रदान करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की थी।

32 संक्षेप में, "एसपीवी"। 33 सुप्रा नोट 18.

34 संक्षेप में, "एस. बी. आई. पी. एल"।

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। [संजीव खन्ना, जे.] 366 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

365

एस. बी. पी. आई. एल. की सहयोगी कंपनी श्री बजरंग मेटालिक्स एंड पावर लिमिटेड 36 द्वारा कैप्टिव उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर 35 की प्रणाली। एस. बी. एम. पी. एल. के पास एस. बी. पी. आई. एल. में 27.6% इक्विटी शेयर थे। हालाँकि, फैसले में यह भी कहा गया है कि एस. बी. एम. पी. एल. के सी. जी. पी. में सीधे 26.67% शेयर थे। 37 सी. एस. पी. डी. सी. एल. ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि एस. बी. पी. आई. एल. और एस. बी. एम. पी. एल. द्वारा स्वतंत्र रूप से/व्यक्तिगत रूप से बिजली की खपत सी. जी. पी. के उनके संबंधित स्वामित्व के अनुपात में नहीं थी। एस. बी. पी. आई. एल. को सी. जी. पी. में 72 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हुए, उत्पादित बिजली का 14.16% उपभोग करना था, जबकि एस. बी. एम. पी. एल., जिसकी सी. जी. पी. में 26.67% हिस्सेदारी थी, को उत्पन्न बिजली का 57.87% उपभोग करना था।

23. यह न्यायालय वितरण लाइसेंसधारी की याचिका और तर्क से सहमत नहीं था। संयंत्र को सी. जी. पी. और एस. बी. एम. पी. एल. को कैप्टिव उपयोगकर्ता माना गया था। नियमों के नियम 3 (1) (ए) के तहत आवश्यकता दोगुनी है। पहला, कैप्टिव उपयोगकर्ता के पास सी. जी. पी. में 26 प्रतिशत

से कम स्वामित्व नहीं होना चाहिए। दूसरा, कैप्टिव उपयोगकर्ता को ऐसे सी. जी. पी. द्वारा उत्पन्न कुल बिजली का कम से कम 51 प्रतिशत उपभोग करना चाहिए। नियमों के नियम 3 (1) (ए) (ii) के दूसरे परंतुक में कहा गया है कि व्यक्तियों के संघ के मामले में, कैप्टिव उपयोगकर्ता (ओं) के पास कुल मिलाकर संयंत्र का 26 प्रतिशत से कम स्वामित्व नहीं होगा और कैप्टिव उपयोगकर्ता (ओं) सी. जी. पी. के स्वामित्व में अपने शेयरों के अनुपात में वार्षिक आधार पर निर्धारित बिजली का 51 प्रतिशत से कम उपभोग नहीं करेंगे। निर्णय में कहा गया है कि कॉर्पोरेट निकायों का एक संघ एक बिजली संयंत्र स्थापित कर सकता है। एस. बी. एम. पी. एल. के पास एस. बी. पी. आई. एल. में 27.6% इक्विटी शेयर थे और इस प्रकार इसने 26 प्रतिशत की स्वामित्व आवश्यकता को पूरा किया। बिजली की खपत के संबंध में दूसरी आवश्यकता को पूरा किया गया क्योंकि एस. बी. एम. पी. एल. और एस. बी. पी. आई. एल. मिलकर उत्पन्न बिजली का 51 प्रतिशत से अधिक खपत करेंगे।

38

35 संक्षेप में सी. एस. पी. डी. सी. एल.। 36 संक्षेप में, "एस. बी. एम. पी. एल."।

37 फैसले में कहा गया है कि, "अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि एस. बी. पी. आई. एल. के पास कंपनी के 72 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं। हालांकि, इसकी खपत केवल 14.16% (13.22 MU) तक सीमित होगी, जबकि SBMPL होल्डिंग 26.67% शेयरों की खपत 57.87% (54 MU) होगी। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह आनुपातिक नहीं था

बिजली संयंत्र के स्वामित्व के लिए "। स्पष्टीकरण 1 से नियम 3 के प्रावधान में कहा गया है कि किसी कंपनी की होल्डिंग या सहायक कंपनी द्वारा उपभोग, जो एक कैप्टिव उपयोगकर्ता है, भी कैप्टिव उपभोग के रूप में स्वीकार्य होगा।

38 फुटनोट 37 देखें।

24. छत्तीसगढ़ राज्य बिजली 39 के अनुपात में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

और विस्तार। हमने नियमों के नियम 3 (1) (ए) के दूसरे परंतुक के संदर्भ में आनुपातिकता के नियम की अपनी व्याख्या पर मुद्दे I और II में इस तरह का स्पष्टीकरण और विस्तार प्रदान किया है।

25. अधिनियम की धारा 2 (8) के साथ पठित धारा 9 के तहत सी. जी. पी. के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, नियमों के पैराग्राफ (i) और (ii) से नियम 3 (1) (ए) की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। हम पहले ही अधिनियम की धारा 2 (8) के तहत एक सी. जी. पी. की अवज्ञा का उल्लेख कर चुके हैं जो "मुख्य रूप से अपने उपयोग के लिए" शब्दों का उपयोग करता है। इस अभिव्यक्ति को नियमों के नियम 3 के तहत वैधानिक आधार दिया गया है। नियम 3, जैसा कि बार-बार देखा गया है, दो अलग-अलग आवश्यकताओं को शामिल करता है। पहली आवश्यकता यह है कि कैप्टिव उपयोगकर्ता (ओं) के पास सी. जी. पी. में कम से कम 26 प्रतिशत स्वामित्व होना चाहिए। न्यूनतम सीमा या न्यूनतम 26 प्रतिशत स्वामित्व निर्धारित किया गया है। स्वामित्व की ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। दूसरी आवश्यकता न्यूनतम बिजली की खपत से संबंधित है। 51% कुल मिलाकर या उससे अधिक उत्पादित बिजली की खपत उपयोगकर्ता (ओं) द्वारा की जानी चाहिए जो स्वामित्व आवश्यकता को पूरा करता है।

26. नियमों के नियम 3 (1) (ए) के पैराग्राफ (1) और (2) में "कम से कम" शब्दों की उपस्थिति दर्शाती है और दर्शाती है कि 26 प्रतिशत स्वामित्व और 51 प्रतिशत खपत के संबंध में शर्तें न्यूनतम या न्यूनतम सीमा हैं। अधिकतम निर्धारित नहीं है। एक कैप्टिव उपयोगकर्ता जो सी. जी. पी. का 100% का मालिक है और ऐसे संयंत्र से उत्पन्न 51 प्रतिशत या उससे अधिक बिजली की खपत करता है, निर्धारित मापदंडों को पूरा करेगा। समान रूप से, एक कैप्टिव उपयोगकर्ता जिसके पास सी. जी. पी. का 26 प्रतिशत हिस्सा है और जो उत्पन्न बिजली का 51 प्रतिशत या उससे अधिक उपभोग करता है, वह कैप्टिव उपयोगकर्ता के रूप में योग्य होगा। हालाँकि, इसके परिणामस्वरूप दुरुपयोग या जुआ हो सकता है जहाँ अलग-अलग शेयरधारिता वाले कई मालिक हैं। व्यक्तियों के संघ के मामले में, एक ऐसी स्थिति जो प्रथम स्पष्टीकरण द्वारा कवर की जाती है। इस पहलू की, जब कई मालिक होते हैं, व्यक्तियों के संघ के मामले में, अंक II के तहत जांच की जाती है।

27. स्पष्टीकरण 1 से नियम 3 के खंड (बी) के प्रावधान में कहा गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अवहेलना करने वाली सहायक या धारक कंपनी द्वारा उपभोग, जब उनमें से एक बंदी उपयोगकर्ता है, तब भी स्वीकार्य होगा:

39 सुप्रा नोट 18.

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। [संजीव खन्ना, जे.]
368

367

बंदी उपयोगकर्ता द्वारा बंदी उपभोग। स्पष्टीकरण 1 से नियम 3 के खंड (बी) में कहा गया है कि बंदी उपयोगकर्ता बिजली का अंतिम उपयोगकर्ता है। बंदी उपयोगकर्ता वह वास्तविक उपभोक्ता है जो अपने उपयोग के लिए बिजली का उपयोग करता है।

28. नियमों के नियम 3 (1) (ए) का पहला प्रावधान पंजीकृत सहकारी समिति द्वारा स्थापित सी. जी. पी. के मामले में लागू होता है। ऐसे मामलों में, अनुच्छेद (i) और (ii) से नियम 3 (1) (ए) के तहत आवश्यकताओं को सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से संतुष्ट माना जाता है। इसलिए, यदि सहकारी समिति के सदस्य सामूहिक रूप से उत्पन्न बिजली का 51 प्रतिशत से अधिक उपभोग करते हैं, तो बिजली संयंत्र को सी. जी. पी. माना जाएगा और सहकारी समिति के सदस्यों को बंदी उपयोगकर्ता माना जाएगा। सहकारी समिति कुल उत्पादित बिजली का 49 प्रतिशत या उससे कम तीसरे पक्ष को आपूर्ति कर सकती है। कोई भी तीसरा पक्ष, जो सहकारी समिति का सदस्य नहीं है, एक गैर-बंदी उपयोगकर्ता और एक उपभोक्ता होगा, जो लागू होने पर क्रॉस-सब्सिडी और अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। सहकारी समिति के सदस्य जब सामूहिक रूप से उपभोग की आवश्यकता को पूरा करते हैं तो वे क्रॉस-सब्सिडी या अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, चाहे वे समर्पित पारेषण लाइनों का उपयोग करें या वितरण लाइसेंसधारी के वितरण नेटवर्क का उपयोग करके अपने अधिकार का प्रयोग करें। यदि वे अपने वितरण नेटवर्क का उपयोग करते हैं तो वे वितरण लाइसेंसधारक को व्हीलिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

29. नियमों के नियम 3 (1) (ए) का दूसरा प्रावधान उन मामलों में लागू होता है जहां बंदी उपयोगकर्ता "व्यक्तियों का संगठन" है। हम अंक II में नियम 3 (1) (ए) के दूसरे प्रावधान की व्याख्या करते हुए "व्यक्तियों के संगठन" के लिए पात्रता आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

30. दो गौण, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे विचार के लिए उठते हैं।

31. सबसे पहले, हमारे सामने एक तर्क उठाया गया था कि चूंकि की धारा 2 (8)

अधिनियम इस अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, "किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थापित बिजली संयंत्र", बंदी

नियमों के नियम 3 (1) (ए) के तहत उपयोगकर्ता वह व्यक्ति होना चाहिए जिसने संयंत्र की स्थापना में भाग लिया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि "स्थापित" में बिजली संयंत्र की स्थापना के बाद शेयरों/स्वामित्व का अधिग्रहण शामिल नहीं है। इसलिए, स्वामित्व के हस्तांतरण के माध्यम से बंदी स्थिति का हस्तांतरण अधिनियम के तहत निषिद्ध है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

32. हमें कई कारणों से इस याचिका को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अधिनियम की धारा 2 (8) में उपयोग की गई "स्थापना" अभिव्यक्ति को प्रारंभिक स्थापना के संदर्भ में पांडित्यपूर्ण तरीके से नहीं पढ़ा जाना चाहिए। हमें व्यावहारिक वास्तविकता को पहचानना चाहिए और इस व्याख्या के अव्यावहारिक अस्वाभाविक परिणामों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अधिनियम की धारा 2 (8) को सी. जी. पी. की स्थापना के बाद स्वामित्व के हस्तांतरण के निषेध को निहित रूप से शामिल करने के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इस बार को स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है और इसका उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि विधायिका इसे सरल शब्दों में कह सकती थी। बल्कि, धारा 9 (1) में

उपयोग किए गए शब्द हैं, "एक कैप्टिव उत्पादन का निर्माण, रखरखाव या संचालन।

पौधा"। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत सी. जी. पी. के निर्माण, रखरखाव या संचालन को अलग-अलग पढ़ा जा सकता है। यह उपयोग से निकलता है

खंड में "निर्माण, रखरखाव या संचालन" के संदर्भ में शब्द "या"

9(1). यह विधायी इरादे के अनुरूप तर्कसंगत और उचित व्याख्या होगी। यह आवश्यक नहीं है कि सी. जी. पी. का रखरखाव और संचालन करने वाले व्यक्ति ने भी सी. जी. पी. का निर्माण किया होगा। निर्माण, रखरखाव या संचालन अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। इसे नियमों के नियम 3 में लाया गया है जो कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के लिए पात्रता मानदंड को निर्दिष्ट करता है। नियम 3 सी. जी. पी. में बंदी उपयोगकर्ता के स्वामित्व के प्रतिशत और वित्तीय वर्ष में बंदी उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग/खपत को संदर्भित करता है।

33. स्पष्टीकरण 1 से नियम 3 के खंड (सी) में कहा गया है कि किसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा स्थापित उत्पादन केंद्र या बिजली संयंत्र के संबंध में स्वामित्व का अर्थ है मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी पूंजी। अन्य मामलों में, स्वामित्व का अर्थ है उत्पादन केंद्र या बिजली संयंत्र पर स्वामित्व हित और नियंत्रण।

34. धारा 9 (2) में उपयोग किए गए शब्द "प्रत्येक व्यक्ति, जिसने एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का निर्माण किया है और इस तरह के संयंत्र का रखरखाव और संचालन करता है" हैं।

अभिव्यक्ति, "प्रत्येक व्यक्ति" एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित कर सकता है जो सी. जी. पी. का निर्माण नहीं करते हुए सी. जी. पी. का रखरखाव और संचालन करता है, जिसका अर्थ और व्याख्या धारा 9 (1) की भाषा से संबंध प्राप्त करती है जो

यह बताता है कि "एक व्यक्ति एक बंदी का निर्माण, रखरखाव या संचालन कर सकता है।

उत्पादन संयंत्र"। अस्पष्टता के मामले में, व्याख्या के उद्देश्य और उद्देश्य नियम को लागू करना उपयोगी है। एक व्यावहारिक व्याख्या बेहतर है, ताकि विधायी इरादे पर हावी न हो। अदालत के लिए यह मान लेना वैध है कि विधायिका वास्तविकता को जानती है और व्यावहारिक कानूनों का समर्थन और अधिनियमन करती है जो व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित और बढ़ावा देते हैं।

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। [संजीव खन्ना, जे.]
370

369

35. अधिनियम की धारा 2 (49) के तहत व्यक्त "व्यक्ति" अभिव्यक्ति में अन्य बातों के साथ-साथ निगमित निकाय और व्यक्तियों का संघ या निकाय शामिल हैं, चाहे वे निगमित हों या नहीं। कंपनियों और व्यक्तियों के संघ के मामले में स्वामित्व का हस्तांतरण एक सामान्य घटना और व्यवसाय की घटना है।

36. कडोदरा पावर 40 में इस मुद्दे की जांच की गई थी और यह देखा गया है:

“क्या सी. जी. पी. के स्वामित्व को इसकी स्थापना के बाद हस्तांतरित किया जा सकता है?:

xx

xx

xx

21. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यहाँ "स्थापित" शब्द महत्वपूर्ण हैं और यह कि जिस व्यक्ति ने अकेले संयंत्र स्थापित किया है, वह कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का मालिक हो सकता है, न कि उस व्यक्ति (ओं) का जो मूल मालिक (ओं) से हस्तांतरणकर्ता है। आयोग ने विवादित आदेश में इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। न ही यह प्रस्ताव हमें आकर्षित करता है। अधिनियम में कहीं भी यह निर्धारित नहीं किया गया है कि एक बार किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा स्थापित एक कैप्टिव

उत्पादन संयंत्र को दूसरे मालिक को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। न ही अधिनियम यह कहता है कि स्वामित्व के हस्तांतरण पर कैप्टिव उत्पादन संयंत्र अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के बावजूद कैप्टिव होने का अपना चरित्र खो देगा। अधिनियम की धारा 9 जो बंदी पीढ़ी की अनुमति देती है, निम्नलिखित शब्दों से शुरू होती है: इसके बावजूद

इस अधिनियम में कुछ भी निहित है, व्यक्ति एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र और समर्पित पारेषण लाइनों का निर्माण, रखरखाव या संचालन कर सकता है।

स्पष्ट रूप से एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का मालिक वह नहीं होना चाहिए जो निर्माण करता है। धारा 2 (8) में इन शब्दों के उपयोग को धारा 9 में "निर्माण, रखरखाव या संचालन" के बराबर बनाया गया है। जैसा कि हम इसे देखते हैं कि एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्वामित्व या स्वामित्व के किसी भी हिस्से के हस्तांतरण से अपना चरित्र नहीं खोता है बशर्ते कि उत्पादन संयंत्र मुख्य रूप से अपने मालिकों के उपयोग के लिए बिजली का उत्पादन करता है। ऊपर उद्धृत विनियमन सी. जी. पी. द्वारा उत्पन्न बिजली के उपयोगकर्ता पर और प्रतिबंध लगाता है। यदि सी. जी. पी. से कैप्टिव उत्पादन और खपत को नियंत्रित करने वाले अधिनियम और विनियमों के सभी प्रावधानों को निर्दिष्ट किया जाता है तो इस तथ्य के बावजूद एक संयंत्र सी. जी. पी. होगा।

40 शीर्ष टिप्पणी 5.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

कि वर्तमान में संयंत्र उस व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं है जिसने मूल रूप से संयंत्र स्थापित किया था।”

हम उक्त व्याख्या और तर्क से सहमत हैं। ए. सी. जी. पी. अपने स्वामित्व या अपने स्वामित्व के किसी भी हिस्से के हस्तांतरण के कारण अपनी बंदी स्थिति नहीं खोता है, बशर्ते कि हस्तांतरणकर्ता, यानी एक नया बंदी उपयोगकर्ता, नियमों के नियम 3 के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का पालन करता हो।

37. ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड और अनदरव में यह न्यायालय। केंद्रीय बिजली

विनियामक आयोग 41 ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार लाइसेंस और अन्य संबंधित मामलों के अनुदान के लिए प्रक्रिया, नियम और शर्तें), विनियम, 2004 का विनियम 6-ए अधिनियम और भारत के संविधान के अंतर्गत था, तर्क दिया था:

“38. जब एक अयोग्यता प्रदान की जाती है, तो इसे बिजली में व्यापार के क्षेत्र में खिलाड़ियों के संबंध में सीमा पर काम करना होता है। हालाँकि, जब एक नियामक कानून को लागू करने की मांग की जाती है, तो प्रतिबंधों और शर्तों को लागू करने की प्राधिकरण की शक्ति का अर्थ उस उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लगाया जाना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। विद्युत ऊर्जा

में उत्पादन, वितरण और आपूर्ति और व्यापार के साथ किसी भी तरह से निपटना देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। जिन निजी खिलाड़ियों को अनुमति दी गई है या जिन्हें इस ओर से लाइसेंस दिया गया है, उन्हें लगाई गई शर्तों को पूरा करना पड़ सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी शर्तें उचित होनी चाहिए। मान लीजिए, आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करना पड़ सकता है।”

देश की अर्थव्यवस्था के लिए बिजली के उत्पादन के महत्वपूर्ण होने से निपटने के लिए, एक संकीर्ण व्याख्या वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर देगी, जिससे तर्कहीन परिणाम मिलेंगे। धारा 2 (8) और धारा 9 (2) को अधिनियम की धारा 9 (1) के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ने की आवश्यकता है। एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या में सी. जी. पी. का एक बाद का मालिक शामिल होगा, जो नियमों के स्पष्टीकरण 1 से नियम 3 के खंड (सी) के अनुसार एक मालिक है।

38. तमिलनाडु पावर 42 में, ए. पी. टी. ई. एल. ने माना था कि कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के लिए न्यूनतम स्वामित्व और उपभोग मानदंड आवश्यक हैं -

41 (2009) 15 एससीसी 570। 42 सुप्रा नोट 6.

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। [संजीव खन्ना, जे.] 372

371

केवल वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 मार्च को संतुष्ट किया जाता है। तमिलनाडु पावर 43 में ए. पी. टी. ई. एल. का मानना है कि यह पूरे वित्तीय वर्ष में सी. जी. पी. की हिस्सेदारी में किसी भी बदलाव और उसके परिणामस्वरूप कैप्टिव स्थिति के लिए जिम्मेदार होगा। यह देखा जाता है:

“292. हमारे लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत औसत की अवधारणा को लागू करने की स्थिति में कैप्टिव उपयोगकर्ताओं और सी. जी. पी. के चेहरे पर देखने वाली व्यावहारिक विषम संस्कृतियाँ। हम अपीलार्थी की प्रस्तुतियों से सहमत हैं कि एक कैप्टिव संरचना में हिस्सेदारी की प्रकृति सहज और गतिशील है। कि, उक्त कैप्टिव संरचना के भीतर मौजूदा कैप्टिव उपयोगकर्ता किसी भी समय कैप्टिव बिजली की खपत के साथ अपने स्वामित्व को छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं यदि वह उसी के लिए कोई उपयोग नहीं मानता है। ऐसे परिदृश्य में, यदि कोई नया कैप्टिव उपयोगकर्ता नहीं जोड़ा जाता है तो उपभोग के साथ शेयरधारिता को तदनुसार समायोजित किया जाता है। एक सी. जी. पी. भविष्य का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है और यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि उसके कितने शेयरधारक कैप्टिव पावर की खपत के साथ अपने स्वामित्व को छोड़ सकते हैं, न ही यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि क्या किसी नए/कितने कैप्टिव उपयोगकर्ता (ओं) को संरचना के भीतर शामिल किया जाएगा। ऐसे परिदृश्य में, यदि नियमों के नियम 3 के संदर्भ में न्यूनतम खपत के साथ न्यूनतम हिस्सेदारी का सत्यापन वार्षिक रूप से, वित्तीय वर्ष के अंत में नहीं किया जाता है, लेकिन वर्ष के दौरान अलग-अलग अवधि में स्वामित्व को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, तो यह सी. जी. पी. के लिए अपनी कैप्टिव संरचना को बनाए रखने के लिए अप्रत्याशित मतभेद पैदा करेगा। इस प्रकार, हमारा मानना है कि नियम 3 के तहत अनिवार्य

सत्यापन वित्तीय वर्ष के अंत में मौजूदा शेयरधारिता पर विचार करके वार्षिक रूप से किया जाना चाहिए। यह विवादित आदेश के एक हिस्से के रूप में टी. एन. ई. आर. सी. द्वारा तैयार किए गए प्रारूप-5 के अवलोकन से भी स्पष्ट है, जो विशिष्ट रूप से वित्तीय वर्ष के अंत में मौजूदा हिस्सेदारी के अनुसार सत्यापन करने पर भी विचार करता है। इसी तरह का दृष्टिकोण हम पहले ही अपील में ले चुके हैं।

"प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड बनाम एम. पी. ई. आर. सी". शीर्षक से 2018 का सं. 02 और 179 & ओआरएस "(ऊपर)।

xx

xx

xx

43 शीर्ष टिप्पणी 6.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

294. हमारी शर्तों के आलोक में, हम यह भी देखते हैं कि मान लीजिए कि दस (10) कैप्टिव उपयोगकर्ता हैं जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अधिनियम की धारा 9 के तहत कैप्टिव उपयोग के लिए खुली पहुंच का लाभ उठाते हैं, और यदि ऐसे कैप्टिव उपयोगकर्ताओं में से तीन (3) छह महीने के बाद कैप्टिव बिजली प्राप्त करना बंद कर देते हैं, और इसके बजाय तीन नए कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को कैप्टिव संरचना के भीतर मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरधारिता की सदस्यता देकर पेश किया जाता है, तो जब कैप्टिव स्थिति का सत्यापन ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत में मौजूद शेयरधारिता के आधार पर सालाना किया जाएगा, तो उस मामले में पूरे वित्तीय वर्ष में कैप्टिव उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या तेरह (7 + 3 + 3) मानी जाएगी और नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन तीन कैप्टिव उपयोगकर्ताओं ने कैप्टिव बिजली प्राप्त करना बंद कर दिया है, उनकी हिस्सेदारी शून्य/शून्य नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्होंने पहले छह महीनों के लिए कैप्टिव बिजली प्राप्त की थी। नियमों के नियम 3 (1) (ए) (आई) और (2) के तहत शर्त का सत्यापन करते समय, कैप्टिव पावर का उपभोग कैप्टिव उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए जिनकी न्यूनतम 26 प्रतिशत हिस्सेदारी हो। इसलिए, यदि किसी बंदी उपयोगकर्ता की हिस्सेदारी को वित्तीय वर्ष में कुछ महीनों के बाद शून्य/शून्य माना जाता है, तो ऐसे उपयोगकर्ता को बंदी शक्ति का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिससे सीएसएस के भुगतान से छूट की मांग की जा सके। किसी भी स्थिति में, सी. एस. एस. की प्रयोज्यता 2013 की अपील संख्या 38 में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी निर्भर करेगी, जिसका शीर्षक 'एम/एस' है। स्टील फर्नेस एसोसिएशन

भारत बनाम पी. एस. ई. आर. सी. और ए. एन. आर. '

39. हम सहमत नहीं हैं। स्वामित्व की न्यूनतम सीमा, जो 26 प्रतिशत है, को पूरे वर्ष पूरा और संतुष्ट किया जाना है, न कि केवल वित्तीय वर्ष के अंत में। तमिलनाडु पावर 44 में तर्क इस बात की अनदेखी करता है कि नियमों के नियम 3 (1) (ए) के पैराग्राफ (i) और (ii) के बीच एक संबंध है। पैराग्राफ (ii) जो कैप्टिव उपयोगकर्ताओं द्वारा खपत की जाने वाली न्यूनतम बिजली को संदर्भित करता है, उक्त नियम के पैराग्राफ (i) में निर्दिष्ट न्यूनतम स्वामित्व के संदर्भ में है। इस प्रकार, न्यूनतम स्वामित्व आवश्यकता को न्यूनतम बिजली के साथ, पूरे वित्तीय वर्ष में, यानी वर्ष के 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक, लगातार बनाए रखने की आवश्यकता है।

44 शीर्ष टिप्पणी 6.

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। [संजीव खन्ना, जे.] 374

373

उपभोग आवश्यकताएँ। यह नियमों के नियम 3 (1) (बी) के स्पष्टीकरण (2) का अधिदेश भी है, जो बंदी उपयोगकर्ताओं पर नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ए) और (बी) का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व डालता है।

40. बिजली की खपत की गणना और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं की हिस्सेदारी में परिवर्तन का मुद्दा, जब एक सी. जी. पी. में एक से अधिक कैप्टिव उपयोगकर्ता होते हैं और नियम 3 (1) (ए) के दूसरे परंतुक के संदर्भ में आनुपातिकता सिद्धांत के अनुप्रयोग को हमने अंक 2 में निपटाया है।

अंक II. नियमों के नियम **3 (1) (ए)** के लिए दूसरे परंतुक का अनुप्रयोग।

41. दूसरा प्रावधान एक अतिरिक्त पात्रता आवश्यकता प्रदान करता है जहां बंदी उपयोगकर्ता "व्यक्तियों का एक संघ" हैं। शुरुआत में, हमें यह दर्ज करना चाहिए कि परंतुक अस्पष्ट और भ्रमित करने वाला है। इसमें कहा गया है कि कैप्टिव उपयोगकर्ता होने के मामले में कैप्टिव उपयोगकर्ता के पास कुल मिलाकर संयंत्र के स्वामित्व का कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सा होगा और ऐसे कैप्टिव उपयोगकर्ता वार्षिक आधार पर उत्पन्न बिजली के 51 प्रतिशत से कम का उपभोग नहीं करेंगे। इस हद तक, यह नियम 3 (1) (ए) के पैराग्राफ (i) और (ii) की सटीक प्रतिकृति है। इसके बाद, अंतिम भाग में पर्याप्त x में कहा गया है कि कैप्टिव उपयोगकर्ता (ओं) द्वारा रखे गए शेयरों का अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता के भीतर उत्पन्न बिजली की खपत के अनुपात में होना चाहिए।

42. कडोदरा पावर 45 में, आनुपातिकता आवश्यकता का उल्लेख करते हुए, यह माना जाता है:

“उपभोग की आनुपातिकता का आकलन कैसे किया जाना चाहिए:

17. विद्युत नियम 2005 में निर्धारित किया गया है कि वार्षिक आधार पर निर्धारित सी. जी. पी. द्वारा उत्पन्न कुल बिजली का कम से कम 51 प्रतिशत कैप्टिव उपयोग के लिए खपत किया जाता है। हालाँकि, यदि एक से अधिक मालिक हैं तो उपभोग में आनुपातिकता का एक और नियम है। यदि बिजली संयंत्र एक सहकारी समिति द्वारा स्थापित किया जाता है तो 51 प्रतिशत उपयोग की शर्त

को सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से पूरा किया जा सकता है। हालाँकि, यदि यह 'व्यक्तियों का संगठन' है तो बंदी उपयोगकर्ताओं को कम से कम रखने की आवश्यकता है

45 शीर्ष टिप्पणी 5.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

26% संयंत्र के स्वामित्व और ऐसे कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को बिजली संयंत्र के स्वामित्व के हिस्से के अनुपात में वार्षिक आधार पर निर्धारित बिजली का कम से कम 51 प्रतिशत उपभोग करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सी. जी. पी. 10,000 के. डब्ल्यू. एच. बिजली का उत्पादन करता है, तो सी. जी. पी. के मालिकों द्वारा 5100 के. डब्ल्यू. एच. की खपत की आवश्यकता होती है। यदि तीन मालिकों के पास समान हिस्सेदारी है, तो प्रत्येक को + 10 प्रतिशत की भिन्नता के भीतर 5100 किलोवाट घंटे का एक तिहाई उपभोग करना चाहिए, यानी 1530 किलोवाट घंटे से 1870 किलोवाट घंटे के बीच। उत्पादन के 100% पर खपत की आनुपातिकता का आकलन करना उचित नहीं होगा। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग ने कुल खपत के उपयोग के अनुपात की गणना की है जो उत्पादन के 51 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।”

हम कडोदरा पावर 46 में उक्त तर्क से सहमत हैं, लेकिन हम अपीलार्थी-दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम. जी. रामचंद्रन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और चित्रों का उल्लेख करके उक्त तर्क पर विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे।

43. नियमों के नियम 3 (1) (ए) के दूसरे परंतुक का अंतिम भाग, अर्थात् आनुपातिकता सिद्धांत, एक एकात्मक योग्यता अनुपात है। एकात्मक अर्हता अनुपात उपभोग आवश्यकता को शेयरधारिता आवश्यकता से विभाजित करता है, अर्थात् 51 प्रतिशत को 26 प्रतिशत से विभाजित करता है। इसका मतलब है कि सी. जी. पी. की प्रत्येक 1 प्रतिशत हिस्सेदारी के मालिक के पास सी. जी. पी. द्वारा उत्पन्न बिजली की न्यूनतम 1.96% खपत होनी चाहिए, जिसमें + 10 प्रतिशत की भिन्नता की अनुमति है। इसलिए, एकात्मक योग्यता अनुपात 1.764% से 2.156% की सीमा के भीतर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हम उत्पन्न बिजली के 100% को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसके बजाय, हम बिजली की खपत पर हिस्सेदारी की आवश्यकता को लागू करते हैं, जो कुल मिलाकर 26 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, जो 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, और इस तरह गणना करते हैं कि क्या स्वामित्व मानदंड और आनुपातिक खपत मानदंड संतुष्ट हैं। किसी भी तरह से 10 प्रतिशत की भिन्नता का लाभ दिया जाना चाहिए।

44. स्पष्टता के लिए, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम. जी. रामचंद्रन द्वारा दिए गए चित्र नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

46 शीर्ष टिप्पणी 5.

कुल पीढ़ी			100%		
कुल पीढ़ी			100%		
एकात्मक अर्हता अनुपात यह है कि उपभोक्ता आयोन पुनर्प्राप्ति आवश्यकता (10 प्रतिशत की भिन्नता के साथ) अर्थात 51 प्रतिशत को 26 प्रतिशत से विभाजित किया जाता है जो प्रत्येक 1 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए एक कैप्टिव उपयोगकर्ता द्वारा 1.96% खपत के बराबर होता है।					
उपभोग आवश्यकता (कम से कम नहीं)			51%		
शेयरधारिता आवश्यकता (इससे कम नहीं)			26%		
शेय रधा रक	वास् तवि क उप भोग	वास् तवि क हिस् सेदा री	एका त्म क अनु पात प्राप्त किय ा गया	टिप् पणि यां	परि णाम
चित्रण 1					
ए.	20	10.2	1.96		
ए, बी, सी, डी, और ई (सभी) जी में 1 प्रतिशत हेक्टेयर के लिए 1.96% से कम का उपभोग नहीं करते हैं और इसलिए सभी कैप्टिव			ए से ई कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के रूप में योग्य हैं		

उपयोगकर्ताओं के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं। सभी के पास सामूहिक रूप से 26 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है।			
बी.	20	10.2	1.96
सी.	20	10.2	1.96
डी.	20	10.2	1.96
ई.	20	10.2	1.96
अन्य	0	49	0

चित्रण 2

ए.	15	7	2.14
ए, बी, सी, डी और ई (सभी) 1 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 1.96% से अधिक का उपभोग करते हैं और इसलिए सभी कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं। सभी के पास सामूहिक रूप से 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है।			ए से ई कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के रूप में योग्य हैं
बी.	15	6	2.5
सी.	15	5	3
डी.	15	4	3.75
ई.	15	4	3.75
अन्य	25	74	-

चित्रण 3

ए.	30	10	3
ए, बी. ए. एन. डी. सी. 1 प्रतिशत हिस्सेदारी के 1.96% से कम के अनुपात में कैप्टिव कौन को उनकी हिस्सेदारी के लिए योग्य बनाता है। डी का अनुपात 1.96 से ऊपर नहीं है, फिर भी यह इसके लिए योग्य है।			ए से डी कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं। ई कैप्टिव उपयोगकर्ता नहीं है।
बी.	30	10	3
सी.	20	10	2
डी.	5.7 5	3	1.92

ई.	5	3	1.67
10 प्रतिशत भिन्नता की अनुमेय सीमा। ई योग्य नहीं है क्योंकि एकात्मक खपत केवल 1.67% है, अर्थात् जी में 1.96% प्रति 1 प्रतिशत हेक्टेयर से कम है और यह 10 प्रतिशत भिन्नता के भीतर नहीं आती है। ई को छोड़कर ए, बी, सी और डी की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत यानी 26 प्रतिशत से कम नहीं है। अतः ए, बी, सी और डी कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं। ई की अयोग्यता ए, बी, डी और डी को प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि वे संचयी रूप से 51 प्रतिशत से अधिक उपभोग करते हैं और 33 प्रतिशत यानी 26 प्रतिशत से कम नहीं रखते हैं।			
अन्य	9.25	64	-
चित्रण 4			
ए.	25	6	4.17
ए, बी, सी. ए. एन. डी. 1 प्रतिशत		कोई भी कैप्टिव उपयोगकर्ता के रूप में योग्य	

हिस्सेदारी के लिए 1.96% से कम के अनुपात में कैप्टिव कॉन एस. यू. एन. क्यू. ए. को उनकी हिस्सेदारी के योग्य बनाता है। ई योग्य नहीं है क्योंकि एकात्मक खपत केवल 1 प्रतिशत है, यानी कम टीएचएएन 1। 9.6 प्रतिशत और 1 प्रतिशत हिस्सेदारी। हालांकि ए, बी, सी और डी की हिस्सेदारी केवल 21 प्रतिशत है।		नहीं है	
बी.	20	5	4
सी.	15	5	3
डी.	10	5	2
ई.	5	5	1
अन्य	25	74	-

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। [संजीव खन्ना, जे.]
378

377

				चूँकि कुल मिलाकर ए, बी, सी और डी के पास कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सेदारी नहीं है, इसलिए बिजली नियम, 2005 के अनुसार, वे बंदी उपयोगकर्ता की स्थिति का दावा नहीं कर सकते हैं।	
				चूँकि कुल मिलाकर ए, बी, सी और डी के पास कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सेदारी नहीं है, इसलिए बिजली नियम, 2005 के	

				अनुसार, वे बंदी उपयोगकर्ता की स्थिति का दावा नहीं कर सकते हैं।	
चित्रण 5					
ए.	30	1	30	कोई भी कैप्टिव उपयोगकर्ता के रूप में योग्य नहीं है	
ए या बी में से कोई भी कैप्टिव उपयोगकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, भले ही वे सामूहिक रूप से 26 प्रतिशत से कम की 51 प्रतिशत से कम की खपत को संतुष्ट करते हैं। बी योग्य नहीं है क्योंकि एकात्मक खपत 1.95% से कम है और 10 प्रतिशत वी अरिएशन के भीतर नहीं है। A या B स्वतंत्र रूप से donotsatisfy वह हा रे हो एल दी एन जी और डी कॉन एस उम्प्ट आई ऑन रे क्यू आई रेम एन टी एस। बिजली नियम, 2005 के नियम 3 (2) के आधार पर, वे बंदी उपयोगकर्ता स्थिति का दावा नहीं कर सकते हैं।					
बी.	21	25	0.84		
अन्य	49	74	-		

एक बार जब उपरोक्त मानक पूरा हो जाता है और संतुष्ट हो जाता है, तो आवश्यकता को पूरा करने वाले व्यक्ति को समूह बंदी उपयोगकर्ताओं के सदस्य के रूप में माना जाएगा।

45. उपरोक्त व्याख्या मालिकों द्वारा "जुआ" की जाँच करती है, जो नियमों के नियम 3 (1) (ए) का दुरुपयोग और दुरुपयोग होगा। खेल के उदाहरण हैं जहां सी. जी. पी. का एक प्रतिशत या एक महत्वहीन शेयरधारक असमान रूप से उत्पन्न बिजली का उपयोग नहीं कर सकता है, जिसमें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

मामला उसे एक समूह बंदी उपयोगकर्ता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और इसलिए, बंदी उपयोगकर्ताओं को अधिनियम के तहत दिए जाने वाले लाभों से वंचित किया जाना चाहिए। वितरण लाइसेंसधारक के हितों की रक्षा के लिए जुआ या दुरुपयोग की जांच की जानी चाहिए।

46. यह हमें उन मामलों में नियम 3 (1) (ए) के दूसरे परंतुक की प्रयोज्यता के सवाल पर लाता है जहां सी. जी. पी. के स्वामित्व या हिस्सेदारी में बदलाव होता है। नियमों के नियम 3 (1) (ए) के

दूसरे प्रावधान के तहत बिजली की आनुपातिक खपत की गणना के संबंध में एक समस्या उत्पन्न होती है जब कोई मौजूदा कैप्टिव उपयोगकर्ता अपनी शेयरधारिता/स्वामित्व को एक नए कैप्टिव उपयोगकर्ता को हस्तांतरित करता है। यह कई स्थितियों में हो सकता है। तमिलनाडु पावर 47 में ए. पी. टी. ई. एल. ने कहा था कि इस तरह के मुद्दे का समाधान तब किया जाएगा जब न्यूनतम खपत और शेयरधारिता आवश्यकताओं का सत्यापन केवल पांचवें वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाएगा। हालाँकि, हमने माना है कि न्यूनतम खपत और शेयरधारिता की आवश्यकता को लगातार बनाए रखने की आवश्यकता है न कि केवल वर्ष के अंत में। केवल बिजली की खपत के अनुपात में स्वामित्व निर्धारित करने के संबंध में ही नियमों के नियम 3 (1) (ए) के दूसरे प्रावधान के संबंध में हमारे ध्यान की आवश्यकता है।

47. स्वामित्व, हिस्सेदारी या खपत में परिवर्तन के मामले में, नियम 3 (1) (ए) के दूसरे प्रावधान के तहत निर्धारित आनुपातिक बिजली खपत आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारित औसत के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई कैप्टिव उपभोक्ता वर्ष के मध्य में अपनी हिस्सेदारी किसी अन्य या नए कैप्टिव उपयोगकर्ता को हस्तांतरित करते हुए बाहर निकलता है या छोड़ देता है, तो यह मानना उचित होगा कि कैप्टिव उपयोगकर्ता जो वर्ष के मध्य में शेयरधारक बन गया है, उसे उत्पन्न बिजली के अनुपात में उपभोग करना आवश्यक है। किसी दिए गए मामले में, मौजूदा कैप्टिव उपयोगकर्ता भिन्नता का लाभ उठाते हुए, अपनी खपत बढ़ा सकते हैं। भारित औसत हिस्सेदारी की अवधारणा वर्ष में कैप्टिव उपयोगकर्ता की प्रासंगिक औसत हिस्सेदारी और उसके द्वारा खपत की जाने वाली आनुपातिक बिजली की गणना करने में सहायता करती है। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसव प्रभु पाटिल द्वारा दिए गए चित्रों से उधार लेने के लिए, यह उन उदाहरणों में सहायता करता है जहां एक कैप्टिव उपयोगकर्ता की शेयरधारिता होती है।

47 शीर्ष टिप्पणी 6.

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। [संजीव खन्ना, जे.] 380

379

सी. जी. पी. फ्लक्च्यूट्स में, बशर्ते कि कुल मिलाकर 26 प्रतिशत की न्यूनतम स्वामित्व आवश्यकता का उल्लंघन नहीं किया जा रहा हो। इसके अलावा, एक शेयरधारक 3 महीने के लिए सी. जी. पी. के 30 प्रतिशत शेयर, 4 महीने के लिए 40 प्रतिशत शेयर और शेष 12 महीनों के लिए 50 प्रतिशत शेयर रख सकता है। भारित औसत शेयरधारिता विधि को नियम 3 (1) (ए) के दूसरे परंतुक के संदर्भ में उसके द्वारा खपत की जाने वाली आनुपातिक बिजली की गणना करने के उद्देश्य से वर्ष के लिए विशेष शेयरधारक द्वारा आयोजित औसत शेयरधारिता लेकर लागू किया जाता है।

48. हम इस तर्क और तर्क से सहमत हैं कि बिजली की भारित हिस्सेदारी और आनुपातिक खपत यह निर्धारित करने के लिए उचित, न्यायसंगत और सही तरीका है कि क्या नियम 3 (1) (ए) के दूसरे परंतुक की आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।

मुद्दा **III** क्या बिजली उत्पादन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन **48** के रूप में स्थापित कोई कंपनी 'व्यक्तियों का संगठन' है जिसे नियमों के नियम **3 (1) (ए)** के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट आनुपातिकता आवश्यकता को पूरा करना चाहिए।

49. यह हमें अंतिम मुद्दे और प्रश्न पर लाता है-क्या नियमों के खंड नियम 3 (1) (बी) को देखते हुए एक एस. पी. वी. के रूप में स्थापित कंपनी, नियमों के नियम 3 (1) (ए) के पैराग्राफ (i) और (ii) में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करने से मुक्त है, जिसे नियमों के नियम 3 (1) (ए) के दूसरे प्रावधान के साथ पढ़ा जाता है। यह तर्क तमिलनाडु पावर 49 में निम्नलिखित आधारों पर उठाया और स्वीकार किया गया था:

“255. हमने ए. ओ. पी. के रूप में एस. पी. वी. के उपचार के मुद्दे पर पक्षों की दलीलों का विश्लेषण किया है। जैसा कि पहले देखा गया है, नियमों का नियम 3 बंदी के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं से संबंधित है। उक्त नियम में, सी. जी. पी. के रूप में एस. पी. वी. नियम 3 (1) (बी) के तहत दिया गया है। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि नियम 3 (1) (ए) (आई) में दो प्रावधान हैं जो इस बात पर विचार करते हैं कि सी. जी. पी. के रूप में अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकताओं को एक पंजीकृत सहकारी समिति और एक ए. ओ. पी. द्वारा पूरा किया जाना है। यह भी देखा गया है कि उक्त दो प्रावधान नियम 3 (1) (बी) से संबंधित नहीं हैं जो एक एस. पी. वी. से संबंधित है।

48 संक्षेप में, "एसपीवी"। 49 शीर्ष टिप्पणी 6.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

256. हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत निवेदन से सहमत हैं कि नियम 3 (1) (ए) का दूसरा परंतुक एक स्वतंत्र प्रावधान है और इस तरह नियम 3 (1) (बी) से संबंधित नहीं है। संसद ने अपने विवेक से नियम 3 के तहत एस. पी. वी. और ए. ओ. पी. के बीच एक समझदारी भरा अंतर पैदा किया है। नियम 3 के पढ़ने से यह स्पष्ट है कि नियम 3 (1) (ए) का दूसरा प्रावधान जो विशेष रूप से ए. ओ. पी. से संबंधित है, यह बताता है कि कैप्टिव उपयोगकर्ता (ओं) के पास कुल मिलाकर संयंत्र का 26 प्रतिशत से कम स्वामित्व नहीं होगा और वे बिजली संयंत्र के अपने स्वामित्व के अनुपात में वार्षिक आधार पर निर्धारित बिजली का 51 प्रतिशत से कम उपभोग नहीं करेंगे।

257. दूसरी ओर, नियम 3 (1) (बी) विशेष रूप से एक एस. पी. वी. से संबंधित है, और यह केवल यह प्रदान करता है कि नियम 3 (1) (ए) (आई) और (2) में उल्लिखित शर्तें एक एस. पी. वी. पर लागू होती हैं, जिसमें दूसरा परंतुक उस पर लागू होना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार, हम अपीलार्थी के तर्क में जोर देते हैं कि नियम 3 (1) (ए) का दूसरा प्रावधान एक स्वतंत्र प्रावधान है।

258. अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क को अदालतों द्वारा कानूनों की व्याख्या के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर और मजबूत किया गया है। माननीय उच्चतम

न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय कानून को फिर से नहीं लिख सकते हैं या उनका पुनर्गठन नहीं कर सकते हैं, उन्हें कानून निर्माताओं के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए जहां कानून के किसी हिस्से में भाषा में कोई अस्पष्टता नहीं है तो ऐसे कानून की शाब्दिक व्याख्या बिना किसी विचलन के की जानी चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना है कि प्रावधान सामान्य नियम के अपवाद हैं। इस संबंध में हम निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख करते हैं:

xx

xx

xx

259. उपरोक्त निर्णयों से प्राप्त सिद्धांतों से, हम देखते हैं कि टी. एन. ई. आर. सी. ने आक्षेपित आदेश को विशेष रूप से पैरा 6 में देखा है।⁴ नियम 3 (1) (बी) में एक इरादा जोड़ने का प्रयास किया है जो अन्यथा इसके निर्माण से अनुपस्थित था। यह अभिनिर्धारित करके कि नियम 3 (1) (ए) का दूसरा परंतुक नियम 3 (1) (बी) पर लागू होता है, जिससे एक एस. पी. वी. की तुलना ए. ओ. पी. से की जाती है, आक्षेपित आदेश ने उक्त नियम की व्याख्या करने में त्रुटि की है जिस तरह से इसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। हम कैलाश नाथ (ऊपर) और संजय कुमार (ऊपर) के मामलों में निर्धारित सिद्धांतों से भी सहमत हैं कि एक परंतुक एक अपवाद है और यह उस प्रावधान से आगे नहीं जा सकता है जिसके लिए यह 381 है।

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। [संजीव खन्ना, जे.] 382

प्रावधान। इसलिए हम मानते हैं कि वर्तमान अपील के तथ्यों में भी यही बात लागू होती है। यह तय कानून है कि एक परंतुक का कार्य अधिनियम से बाहर कुछ को छोड़कर या उसमें अधिनियमित कुछ को अर्हता प्राप्त करना है जो परंतुक के लिए अधिनियम के दायरे में होगा। इस स्पष्ट न्यायशास्त्र को लागू करते हुए, टी. एन. ई. आर. सी. नियम 3 (1) (ए) के दूसरे परंतुक को नियम 3 (1) (बी) पर लागू नहीं कर सकता था। इसलिए, वार्षिक आधार पर उत्पन्न न्यूनतम 51 प्रतिशत बिजली की खपत की आवश्यकता और कुल मिलाकर संयंत्र के स्वामित्व का 26 प्रतिशत रखने वाले कैप्टिव उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता और बिजली संयंत्र के स्वामित्व के शेयरों के अनुपात में ऐसी खपत केवल ए. ओ. पी. द्वारा स्थापित बिजली संयंत्रों पर लागू हो सकती है, लेकिन एस. पी. वी. द्वारा स्थापित बिजली संयंत्रों पर लागू नहीं की जा सकती है।

50. कडोदरा पावर 50 विपरीत दृष्टिकोण रखता है, और एपीटीईएल ने तर्क दिया है:

“क्या एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में बनाई गई कंपनी एक व्यक्ति का संगठन है?

15. सवाल इसलिए उठा है क्योंकि 'व्यक्तियों का संगठन' शब्द अधिनियम या नियमों में कहीं भी लागू नहीं है। नियम 3 (1) (ए) (2) का परंतुक सहकारी समितियों और व्यक्तियों के संघ के लिए दो विशेष शर्तें बनाता है। यदि सी. जी. पी. किसी व्यक्ति के पास है तो यह पर्याप्त है कि वह व्यक्ति ऐसे

संयंत्र में उत्पन्न कुल बिजली का कम से कम 51 प्रतिशत उपभोग करता है। यदि संयंत्र एक पंजीकृत सहकारी समिति के स्वामित्व में है तो सभी सदस्यों को सामूहिक रूप से कुल उत्पादित बिजली का 51 प्रतिशत उपभोग करना होगा। यदि सी. जी. पी. व्यक्तियों के एक संघ के स्वामित्व में है तो बंदी उपयोगकर्ता कुल मिलाकर संयंत्र के स्वामित्व का कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सा रखेंगे और संयंत्र के स्वामित्व के अपने हिस्से के अनुपात में उत्पन्न बिजली का कम से कम 51 प्रतिशत उपभोग करेंगे। एक विशेष प्रयोजन वाहन एक कानूनी इकाई है जो एक उत्पादन केंद्र का स्वामित्व, संचालन और रखरखाव करती है जिसमें कानूनी इकाई द्वारा कोई अन्य व्यवसाय या गतिविधि नहीं की जाती है। अब अगर तीन कंपनियों की जरूरत है

50 शीर्ष टिप्पणी 5.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

मुख्य रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिए बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए वे एक साथ आ सकते हैं और एक अन्य कानूनी इकाई बना सकते हैं जो स्वयं कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी हो सकती है। यह कंपनी एक बिजली संयंत्र स्थापित कर सकती है। उस स्थिति में तीन अलग-अलग कंपनियों द्वारा बनाई गई कंपनी एक विशेष प्रयोजन वाहन बन जाएगी। यदि कोई कंपनी जो एक विशेष प्रयोजन वाहन है, एक व्यक्ति है तो यह आवश्यक है कि इस कंपनी को उत्पादन का 51 प्रतिशत उपभोग करना चाहिए। हालाँकि, यदि इसे अपनी उत्पादन के न्यूनतम 51 प्रतिशत की खपत की शर्त के अलावा व्यक्तियों के संगठन के रूप में माना जाता है, तो तीनों शेयरधारकों को बिजली संयंत्र में अपने स्वामित्व के अनुपात में उत्पादन का 51 प्रतिशत भी उपभोग करना होगा। हमारे समक्ष कुछ अपीलकर्ताओं, जो विशेष प्रयोजन वाहन हैं, की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि वे व्यक्तियों का संगठन नहीं हैं और तदनुसार उनके लिए यह आवश्यक है कि वे अपने हिस्से के उपभोग के आनुपातिकता के नियम का पालन किए बिना सामूहिक रूप से अपनी पीढ़ी का 51 प्रतिशत उपभोग करें। यह हमें सही दृष्टिकोण नहीं लगता है। अधिनियम की धारा 2 (8), जैसा कि ऊपर निकाला गया है, कहती है कि एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थापित किया जा सकता है और इसमें किसी भी सहकारी समिति या व्यक्तियों के संघ द्वारा स्थापित बिजली संयंत्र शामिल है। श्री एम. जी. रामचंद्रन का तर्क है कि इस अवज्ञा के अनुसार यदि विशेष प्रयोजन वाहन व्यक्तियों का एक संघ नहीं है तो यह एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित नहीं कर सकता है क्योंकि अवज्ञा में एक सहकारी समिति और व्यक्ति के संघ के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का उल्लेख नहीं है। श्री एम. जी. रामचंद्रन के तर्क में एक छोटी सी बात है कि कैप्टिव उत्पादन संयंत्र की अवज्ञा समावेशी है। दूसरे शब्दों में, कैप्टिव उत्पादन संयंत्र किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थापित किया जा सकता है जिसमें एक सहकारी समिति या व्यक्तियों का संघ शामिल है। दूसरे शब्दों में, एक उत्पादन संयंत्र स्थापित करने वाला व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी सहकारी समिति या व्यक्तियों के संघ के विवरण को पूरा नहीं करता है। फिर भी, पूरे नियम 3 को समग्र रूप से पढ़ने पर हमें यह प्रतीत होता है कि एक विशेष प्रयोजन वाहन के स्वामित्व वाले सी. जी. पी. को

व्यक्ति के संगठन के रूप में माना जाना चाहिए और संयंत्र के स्वामित्व के अनुपात में अपनी पीढ़ी का 51 प्रतिशत उपभोग करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। प्रत्येक कानूनी इकाई व्यक्ति है। इसलिए, विशेष प्रयोजन वाहन जो 383

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। [संजीव खन्ना, जे.] 384

एक कानूनी इकाई होना चाहिए जो अपने आप में एक व्यक्ति होगा। कोई भी उत्पादन कंपनी या कैप्टिव उत्पादन कंपनी भी एक व्यक्ति होती है। नियम विशेष रूप से सहकारी समिति से संबंधित हैं। व्यक्तियों के एक संघ में इसे एक 'व्यक्ति' होना चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति होने के बिना यह एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि चूंकि विशेष प्रयोजन वाहन अपने आप में एक 'व्यक्ति' है, इसलिए इसे 'व्यक्तियों के संगठन' की अवज्ञा द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है और इसे मुख्य प्रावधान द्वारा कवर किया जाना चाहिए जिसके लिए मालिक को संयंत्र के उत्पादन का 51 प्रतिशत या उससे अधिक उपभोग करने की आवश्यकता होती है। हमारे विचार में परिभाषा कुछ हद तक अजीब है क्योंकि कहा जाता है कि 'व्यक्ति' शब्द में 'व्यक्तियों का संगठन' शामिल है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि एक सी. जी. पी. मालिक या तो एक 'व्यक्ति' या 'व्यक्तियों का संघ' हो सकता है—एक विशेष प्रयोजन वाहन इस प्रकार एक 'व्यक्ति' के साथ-साथ 'व्यक्तियों का संघ' भी हो सकता है। एक सहकारी समिति इस अर्थ में व्यक्तियों का एक संघ है कि कुछ व्यक्ति एक सहकारी समिति बनाने के लिए एक साथ आते हैं। हालाँकि, जिस क्षण कानूनी प्रावधानों के अनुसार एक संघ या समाज का गठन किया जाता है, वह अपने आप में एक व्यक्ति बन जाता है। सहकारी समितियों को सामूहिक रूप से 51 प्रतिशत उपभोग करने की अनुमति देने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। प्रथम परंतुक 3 (1) (ए) (ii) स्वयं सुझाव देता है कि एक सहकारी समिति को एक विशेष विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। अन्य व्यक्ति जो कई व्यक्तियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाए गए कानूनी निकाय भी हैं, उन्हें ऐसा विशेष विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। व्यक्तियों का ऐसा संगठन कौन हो सकता है? सी. जी. पी. के मालिक व्यक्तियों के रूप में समझी जाने वाली विभिन्न कानूनी संस्थाओं में से विशेष प्रयोजन वाहन 'व्यक्तियों के संगठन' का वर्णन करता प्रतीत होता है। हम यह समझने में विफल रहते हैं कि एक विशेष उद्देश्य वाहन के अलावा कौन 'व्यक्तियों का संगठन' हो सकता है। हमारे सामने बहस करने वाले वकीलों में से किसी ने भी विशेष प्रयोजन वाहन के अलावा 'व्यक्तियों के संगठन' का उदाहरण नहीं दिया। इसलिए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि विशेष प्रयोजन वाहन व्यक्तियों का एक संगठन है। 16. यदि उपभोग की आनुपातिकता के नियम को बनाए रखने के लिए विशेष प्रयोजन वाहन की आवश्यकता नहीं थी, तो केंद्र सरकार विशेष रूप से उसी का उल्लेख कर सकती थी जैसा उसने एक सहकारी समिति के लिए किया है। नियम में एक विशेष प्रयोजन वाहन को उत्पादन के 51 प्रतिशत की खपत की आवश्यकता से छूट नहीं दी गई है।

विशेष प्रयोजन वाहन बनाने वाले व्यक्तियों के स्वामित्व का अनुपात, जैसा कि सहकारी समिति के मामले में किया गया है, केवल यह मानना तर्कसंगत और तार्किक होगा कि एक विशेष प्रयोजन वाहन भी 'व्यक्तियों के संघ' के रूप में स्वामित्व के प्रतिशत हिस्से के उपभोग की आनुपातिकता के नियम के अधीन है।

51. हम नियमों के कडोदरा पावर 51 नियम 3 (1) (बी) में दिए गए तर्क से सहमत हैं जो नियमों के पैराग्राफ (i) और (ii) से नियम 3 (1) (ए) में निर्दिष्ट पात्रता आवश्यकताओं को नकारता या पूर्ववत नहीं करता है, जो व्यक्तियों के एक संघ के मामले में नियम 3 (1) (ए) के दूसरे परंतुक के तहत आनुपातिकता आवश्यकता की संतुष्टि को अनिवार्य करता है। नियम 3 (1) (बी) एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक एस. पी. वी. के रूप में स्थापित कंपनी के पास बिजली पैदा करने वाली कई इकाइयाँ हैं। यह निर्धारित करता है कि एस. पी. वी. के रूप में गठित कंपनी अपने कैप्टिव उपयोग के लिए ऐसी एक या अधिक उत्पादन इकाइयों की पहचान कर सकती है। कैप्टिव उपयोग के लिए सभी उत्पादन इकाइयों की पहचान करने की आवश्यकता नहीं है। जिन इकाइयों की पहचान कैप्टिव उपयोग के लिए नहीं की गई है, उन्हें नियमों के नियम 3 (1) (ए) के पैराग्राफ (i) और (ii) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। इन अज्ञात इकाइयों द्वारा उत्पन्न बिजली का हिसाब रखने और उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्टीकरण स्थिति को स्पष्ट करता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि कैप्टिव उपयोगकर्ताओं द्वारा बिजली की खपत की आवश्यकता का निर्धारण कैप्टिव उपयोग के लिए पहचानी जाने वाली उत्पादन इकाई या इकाइयों के संदर्भ में किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, कैप्टिव उपयोग के लिए पहचानी गई इकाई या इकाइयों को दूसरे परंतुक के साथ पढ़े गए नियमों के नियम 3 (1) (ए) के पैराग्राफ (i) और (ii) की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। यह नियम 3 (2) से भी स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि उत्पादन केंद्र में कैप्टिव उपयोगकर्ता द्वारा रखे गए इक्विटी शेयर, जो कैप्टिव उपयोग के लिए पहचाने जाते हैं, उत्पादन इकाई या सी. जी. पी. के रूप में पहचानी जाने वाली इकाइयों से संबंधित कंपनी की आनुपातिक इक्विटी के 26 प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिए। सुविधा के लिए धारा 3 (1) (बी) का स्पष्ट चित्रण फिर से प्रस्तुत किया गया है:

“उदाहरण-50 मेगावाट की दो इकाइयों ए और बी के साथ एक उत्पादन केंद्र में, 50 मेगावाट की एक इकाई ए को कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के रूप में पहचाना जा सकता है। कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के पास कम से कम तेरह प्रतिशत इक्विटी शेयर होंगे।

51 शीर्ष टिप्पणी 5.

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। [संजीव खन्ना, जे.]

कंपनी (50 मेगावाट की इकाई ए के अनुपात में छब्बीस प्रतिशत होने के नाते) और वार्षिक आधार पर निर्धारित इकाई ए में उत्पन्न बिजली का कम से कम 51 प्रतिशत कैप्टिव उपयोगकर्ताओं द्वारा खपत किया जाना है।”

इस प्रकार, नियमों का नियम 3 (1) (बी) उदार बनाता है, एक विकल्प देता है जब एक एस. पी. वी. के रूप में निगमित कंपनी के स्वामित्व वाले एक उत्पादन केंद्र में कई उत्पादन इकाइयाँ होती हैं। नियम 3 (1) (बी) दूसरे परंतुक के साथ पढ़े गए नियम 3 (1) (ए) के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूर्ववत या ओवरराइड नहीं करता है।⁵² हमारे समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि एक एस. पी. वी. एक निगमित कंपनी थी, इसलिए इसे व्यक्तियों के एक संघ के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, जिसका अर्थ आमतौर पर एक मान्यता प्राप्त कर योग्य इकाई के रूप में समझा जाता है न कि एक निगमित इकाई के रूप में। रिलायंस को इस अदालत द्वारा व्याख्या पर रखा गया था

रमनलाल भाईलाल पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य ⁵² में, मुकाबला करने के लिए कि जब भी किसी अवधि के लिए एक समावेशी परिभाषा प्रदान की जाती है, तो ऐसी अवधि की एक विस्तारित वैधानिक व्याख्या को अपनाया जा सकता है। संविधान की धारा 2 (49)

अधिनियम में "शामिल" शब्द का उपयोग किया गया है, अभिव्यक्ति में, "व्यक्ति" में शामिल होगा "

अधिनियम के संबंध में किसी "व्यक्ति" की अवहेलना करना। इस प्रकार "व्यक्तियों का संगठन" शब्द के लिए इस तरह की विस्तारित वैधानिक व्याख्या, जो प्रस्तुत की जाती है, आयकर अधिनियम, 1961 जैसे कानूनों से आयात योग्य है। हम उक्त तर्क से सहमत नहीं हैं।

53. यह न्यायालय रमनलाल भाईलाल पटेल ⁵³ में, की व्याख्या करते हुए

"व्यक्तियों के संघ" के अर्थ में यह माना गया है कि व्यक्तियों का एक संघ वह है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति कुछ सामान्य लाभ प्राप्त करने के लिए एक सामान्य उद्देश्य और सामान्य कार्रवाई में शामिल होते हैं। इसके अलावा, इस तरह के सामान्य उद्देश्य, कार्रवाई या लाभ एक कानून के विशेष संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। संबंधित अनुच्छेद में लिखा है:

“28. "व्यक्तियों का संगठन" और "व्यक्तियों का निकाय" (जो विनिमेय हैं) शब्दों का एक कानूनी अर्थ है और अधिकार और कर्तव्यों वाली इकाई को संदर्भित करता है। उन्हें शाब्दिक रूप से नहीं समझा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आधा दर्जन लोग कार में यात्रा कर रहे हैं

⁵² (2008) 5 एस. सी. सी. 449; संक्षेप में, "रमनलाल भाईलाल पटेल"। ⁵³ सुप्रा नोट 52।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

या नाव, या बस-स्टॉप पर खड़े होकर, वे शाब्दिक अर्थों में व्यक्तियों का एक समूह या "व्यक्तियों का एक समूह" हो सकते हैं। लेकिन वे कानूनी अर्थों में व्यक्तियों/व्यक्तियों के निकाय का संगठन नहीं हैं। जब कोई आपदा आती है या कोई आपदा आती है, और स्वयंसेवकों या डॉक्टरों का एक समूह स्थल पर मिलता है और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए एक-दूसरे के साथ जुड़ता है या सहयोग करता है, और अपने स्वयं के लाभ के लिए कुछ भी नहीं करता है, तो वे शाब्दिक रूप से व्यक्तियों का एक संघ हो सकते हैं, लेकिन वे कानूनी अर्थों में "व्यक्तियों का एक संघ/व्यक्तियों का निकाय" नहीं हैं। केवल व्यक्तियों का संयोजन या बिना किसी चीज़ के व्यक्तियों का एक साथ आना, बिना किसी संयुक्त उद्यम के इरादे के या एक सामान्य समझ और उद्देश्य के साथ कुछ सामान्य गतिविधि करने से दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यक्तियों के निकाय/व्यक्तियों के संघ में परिवर्तित नहीं होंगे। एक "व्यक्तियों का संगठन/व्यक्तियों का निकाय" वह है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति कुछ सामान्य लाभ प्राप्त करने के लिए एक सामान्य उद्देश्य और सामान्य कार्रवाई में शामिल होते हैं। जहां पार्टियों की इच्छा से व्यक्तियों का एक संयोजन होता है, जो किसी संयुक्त उद्यम या उद्यम में एक साथ लगे होते हैं, तो इसे "व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का निकाय" के रूप में जाना जाता है। सामान्य उद्देश्य की यह निर्धारित करने के लिए कुछ प्रासंगिकता होगी कि क्या कोई समूह या व्यक्तियों का समूह किसी विशेष कानून के संदर्भ में व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय है। उदाहरण के लिए, जब उक्त शब्द "व्यक्तियों का संगठन" या "व्यक्तियों का निकाय" किसी ऐसे खंड में आता है जो आय पर कर लगाता है, तो संघ का उद्देश्य आय, लाभ या लाभ उत्पन्न करना होना चाहिए (सी. आई. टी. बनाम इंदिरा बालकृष्ण, मोहम्मद। नूरुल्ला बनाम सी. आई. टी., N.V. Shanmugam और कंपनी बनाम सी. आई. टी. और मीरांद कं. वी.सी. आई. टी.) लेकिन उद्देश्य हमेशा वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधि को जारी रखना नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब "व्यक्ति" शब्द कृषि या भूमि स्वामित्व की सीमा से संबंधित कानून में आता है, तो "व्यक्तियों का संगठन/व्यक्तियों का निकाय" शब्द उन व्यक्तियों के संयोजन को संदर्भित कर सकता है जो सह-मालिक के रूप में भूमि का अधिग्रहण करने और स्वामित्व करने के लिए एक साथ जुड़ते हैं और एक संयुक्त उद्यम के रूप में कृषि कार्यों को जारी रखते हैं।”

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। [संजीव खन्ना, जे.] 388

387

54. इसके अलावा, रमनलाल भाईलाल पटेल 54 में, व्यक्तियों के संघ की धारणा पर विस्तार से बताते हुए, न्यायालय ने कहा कि किसी संपत्ति के सह-मालिक स्वचालित रूप से व्यक्तियों का संघ नहीं बन जाते हैं। जहां ऐसे सह-मालिकों के पास एक सामान्य उद्देश्य की कमी है और वे अपनी इच्छा से नहीं बल्कि सह-स्वामित्व का पीछा करते हैं, ऐसे सह-मालिकों में से प्रत्येक को एकल व्यक्ति के रूप में संदर्भित करने के बजाय व्यक्तियों के संघ/व्यक्तियों के निकाय के रूप में एक अलग व्यक्ति का गठन किया जाएगा। तर्क को पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“29. आम तौर पर, जहां व्यक्तियों का एक समूह एक सामान्य उद्देश्य के साथ अपनी इच्छा से सह-मालिक नहीं बना है, उन्हें "व्यक्ति" नहीं माना जा सकता है। जब किसी संपत्ति के मालिक के बच्चे

वसीयती उत्तराधिकार द्वारा अपनी संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं या कानून के संचालन द्वारा विरासत में मिलते हैं, तो वे सह-मालिक बन जाते हैं, लेकिन सह-स्वामित्व पक्षों की इच्छा से नहीं होता है और न ही उनका कोई सामान्य उद्देश्य होता है। प्रत्येक अपने हिस्से के संबंध में, अपने दम पर, अन्य मालिकों के प्रति किसी भी अधिकार या दायित्व के बिना कार्य कर सकता है। कानूनी उत्तराधिकारी, हालांकि सह-मालिक हैं, स्वचालित रूप से "व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का निकाय" नहीं बन जाते हैं। जब अलग-अलग व्यक्ति भूमि के भूखंड में अविभाजित शेयर खरीदते हैं और संबंधित अपार्टमेंट के संबंध में व्यक्तिगत स्वामित्व और सामान्य क्षेत्रों के संयुक्त स्वामित्व के साथ एक अपार्टमेंट भवन के निर्माण के लिए एक सामान्य डेवलपर को नियुक्त करते हैं, तो भूमि के भूखंड के सह-मालिक, किसी कानून या समझौते में एक डीमिंग प्रावधान के अभाव में, "व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का निकाय" नहीं बन जाते हैं। इसी तरह, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति केवल एक सामान्य बिक्री विलेख के तहत, एक सामान्य या संयुक्त उद्यम के लिए किसी समझौते के बिना एक संपत्ति खरीदते हैं, तो वे "व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का निकाय" नहीं बनेंगे। बिना किसी और चीज के एक सामान्य विलेख के तहत केवल खरीद, एक सह-स्वामित्व को एक संयुक्त उद्यम में परिवर्तित नहीं करेगी। इस प्रकार जब किसी संपत्ति के दस सह-मालिक होते हैं, तो वे दस व्यक्ति होते हैं और "एकल व्यक्ति" के रूप में माने जाने वाले "व्यक्तियों के निकाय" नहीं होते हैं। लेकिन यदि सह-मालिक आगे बढ़ते हैं और अपने लाभ के लिए एक सामान्य परिणाम उत्पन्न करने के लिए एक संयुक्त उद्यम या उद्यम बनाने के लिए एक व्यवस्था या समझौता करते हैं, तो सह-मालिक एक "व्यक्ति" की अवज्ञा का जवाब दे सकते हैं।"

54 सुप्रा नोट 52।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

55. इस प्रकार, अभिव्यक्ति का अर्थ, "व्यक्तियों का संघ", उस विशेष संदर्भ के आधार पर अलग-अलग कानूनों में भिन्न हो सकता है जिसमें उस कानून में व्यक्तियों के संघ का उपयोग किया जाता है। यह जाँचने की आवश्यकता है कि क्या व्यक्तियों का ऐसा संघ उक्त कानून के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक सामान्य कार्रवाई कर रहा है।

56. अधिनियम और नियमों के संदर्भ में, कंपनियां या निकाय निगम एक साथ आ सकते हैं और अधिनियम और नियमों के तहत बंदी उपयोगकर्ता बनने के सामान्य लाभ को प्राप्त करने के लिए एक सामान्य उद्देश्य के साथ एक एसपीवी के रूप में एक अन्य कंपनी की स्थापना कर सकते हैं, जिससे बंदी उपयोगकर्ताओं को प्रदान किए गए लाभों का आनंद लिया जा सके जैसे कि क्रॉस सब्सिडी या अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करने से छूट, जैसा कि लागू हो। 57. इसके अलावा, नियमों के नियम 3 के लिए स्पष्टीकरण 1 (डी), एक एस. पी. वी. का अर्थ एक कानूनी इकाई है जो एक उत्पादन केंद्र का स्वामित्व, संचालन और रखरखाव करती है, जिसमें कानूनी इकाई द्वारा कोई अन्य व्यवसाय या गतिविधि नहीं की जाती है। इस प्रकार, एस. पी. वी. का एक ही उद्देश्य है जैसा कि नियमों के तहत परिकल्पित किया गया है, वह है एक उत्पादन केंद्र का स्वामित्व, संचालन और

रखरखाव। एक एस. पी. वी. अपने आप सी. जी. पी. द्वारा उत्पन्न बिजली का उपभोग नहीं कर सकता है, अर्थात्, यह एक कैप्टिव उपयोगकर्ता नहीं हो सकता है क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य एक उत्पादन केंद्र का स्वामित्व, संचालन और रखरखाव करना है। इस प्रकार, एक एस. पी. वी. की स्थापना में कंपनियों या निकाय निगमों का उद्देश्य और उद्देश्य, जो कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को प्रदान किए गए लाभ का आनंद नहीं ले सकते हैं, ऐसे निकाय निगमों, कंपनियों या अन्य व्यक्तियों के लिए होगा कि वे कैप्टिव उपयोगकर्ता बनने के सामान्य लाभ का आनंद लें।

58. हमारा तर्क अधिनियम की धारा 2 (8) के अनुरूप है, जो सी. जी. पी. की अवहेलना करता है, और जैसा कि ऊपर देखा गया है, सी. जी. पी. को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: i) एकल उपयोगकर्ता सी. जी. पी.-धारा 2 (8) का पहला भाग किसी भी व्यक्ति द्वारा मुख्य रूप से अपने उपयोग के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए स्थापित बिजली संयंत्र को संदर्भित करता है; और

ii) समूह उपयोगकर्ता सी. जी. पी.-धारा 2 (8) के दूसरे भाग में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा मुख्य रूप से अपने उपयोग के लिए बिजली पैदा करने के लिए स्थापित बिजली संयंत्र में किसी भी सहकारी समिति या व्यक्तियों के संघ द्वारा बिजली पैदा करने के लिए स्थापित बिजली संयंत्र शामिल है जो मुख्य रूप से ऐसी सहकारी समिति या संघ के सदस्यों के उपयोग के लिए है।

अधिनियम की धारा 2 (8) के तहत सी. जी. पी. की किसी अन्य श्रेणी को मान्यता नहीं दी गई है।

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। [संजीव खन्ना, जे.] 390

389

59. "व्यक्ति" शब्द, जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (49) में परिभाषित किया गया है, उपयोगकर्ताओं की एक विस्तृत श्रेणी को शामिल करता है, जिसमें कोई भी कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट या संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति शामिल हैं।

60. "व्यक्तियों का संगठन" शब्द को विशिष्ट रूप से नहीं लिया गया है।

अधिनियम की अवहेलना। इसके विपरीत, अभिव्यक्ति, "संघ या निकाय

व्यक्ति, चाहे निगमित हो या नहीं, "व्यक्ति" की परिभाषा में उपयोग किया जाता है।

अधिनियम की धारा 2 (49) के तहत न्यायिक और गैर-न्यायिक दोनों व्यक्तियों को शामिल करने के लिए "व्यक्ति" के दायरे का विस्तार किया गया है।

61. दोहराने के लिए, अधिनियम की धारा 2 (8) सी. जी. पी. की दो श्रेणियों को मान्यता देती है, यानी एकल बंदी उपयोगकर्ता और समूह बंदी उपयोगकर्ता। समूह बंदी उपयोगकर्ताओं के लिए, केवल दो श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं को मान्यता दी जाती है, अर्थात् एक सहकारी समिति और व्यक्तियों का संगठन। नियमों के नियम 3 (1) (ए) का पहला प्रावधान सहकारी समितियों के लिए एक अपवाद बनाता है। इसके लिए सहकारी समिति के सदस्यों को नियमों के नियम 3 (1) (ए) के

पैराग्राफ (i) और (ii) के तहत निर्दिष्ट न्यूनतम स्वामित्व और बिजली खपत आवश्यकताओं को केवल सामूहिक रूप से पूरा करने की आवश्यकता होती है। नियम 3 (1) (ए) का दूसरा प्रावधान, जो व्यक्तियों के संगठन को संदर्भित करता है, ऐसे बंदी उपयोगकर्ताओं को नियमों के नियम 3 (1) (ए) के पैराग्राफ (i) और (ii) के तहत निर्दिष्ट न्यूनतम स्वामित्व और बिजली खपत आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को सी. जी. पी. द्वारा उत्पन्न बिजली का उपभोग करने की भी आवश्यकता होती है, जो सी. जी. पी. के स्वामित्व में उनके व्यक्तिगत शेयरों के अनुपात में 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी, जो 26 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इस प्रकार, नियमों के तहत, सभी समूह बंदी उपयोगकर्ता जो पंजीकृत सहकारी समितियां नहीं हैं, उन्हें नियम 3 (1) (ए) के दूसरे प्रावधान में निर्दिष्ट आनुपातिकता परीक्षण का पालन करना आवश्यक है।

62. एस. सुंदरम पिल्लई और अन्य बनाम वी. आर. पट्टाबिरमन में यह न्यायालय

और अन्य 55 ने माना है कि एक परंतुक चार अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा करता है, जैसा कि नीचे कहा गया है:

“43. हमें इस बिंदु पर अधिकारियों के बाद अधिकारियों को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कानूनी स्थिति स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होती है। संक्षेप में, एक परंतुक चार अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा कर सकता है:

55 (1985) 1 एससीसी 591।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

(1) मुख्य अधिनियम से कुछ प्रावधानों को अर्हता प्राप्त करना या छोड़ देना:

(2) यह अधिनियम को व्यवहार्य बनाने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तों को पूरा करने पर जोर देकर अधिनियम के इरादे की अवधारणा को पूरी तरह से बदल सकता है:

(3) यह अधिनियम में ही इस तरह से अंतर्निहित हो सकता है कि वह अधिनियम का एक अभिन्न अंग बन जाए और इस प्रकार मूल अधिनियम की अवधि और रंग प्राप्त कर सके; और

(4) इसका उपयोग केवल वैधानिक प्रावधान के वास्तविक इरादे को समझाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ अधिनियम में एक वैकल्पिक परिशिष्ट के रूप में कार्य करने के लिए किया जा सकता है।”

तदनुसार, नियमों के नियम 3 (1) (ए) का दूसरा परंतुक विशिष्ट मामला नहीं है। इसे अधिनियम की धारा 2 (8) के तहत अंतर्निहित व्याख्या का परिणाम माना जाना चाहिए, जो कि “मुख्य रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिए” है। अधिनियम की धारा 2 (8) के तहत अधिनियमन को किसी भी मामले में व्यवहार्य बनाने के लिए जहां समूह बंदी उपयोगकर्ता पंजीकृत सहकारी समितियां नहीं हैं, नियमों के नियम 3 (1) (ए) के दूसरे प्रावधान के तहत आनुपातिकता के नियम को एक अनिवार्य शर्त के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

63. यह न्यायालय मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड और अन्य में है।संघ

भारत सरकार और अन्य 56 ने माना कि नियमों के पैराग्राफ (ii) से नियम 3 (1) (ए) के तहत न्यूनतम बिजली खपत की आवश्यकता अधिनियम की धारा 2 (8) के तहत आवश्यकता के अनुरूप है, जिसके तहत बिजली का उत्पादन किया जाता है

सी. जी. पी. "मुख्य रूप से अपने उपयोग के लिए" होना चाहिए।इस प्रकार यह माना गया कि नियम 3 (1)

(क) नियमों को अधिनियम के उद्देश्यों के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है। यह

मोनेट इस्पात 57 में न्यायालय ने कहा:

“14. जब हम अधिनियम की धारा 2 (8) में उत्पादन संयंत्र की अवज्ञा की जांच करते हैं तो इस न्यायालय द्वारा ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड (उपरोक्त) में जो चर्चा की गई है, उसके आलोक में यह मुख्य रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिए या सहकारी समिति के मामले में अपने सदस्यों द्वारा उपयोग के लिए स्थापित करने पर जोर देता है।

56 2017 का सी. ए. सं. 18506-18507 संक्षेप में, "मोनेट इस्पात"।57 सुप्रा नोट 56।

मेसर्स दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स गायत्री शक्ति पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। [संजीव खन्ना, जे.] 392

391

जब हम 2005 के नियमों के नियम 3 (1) (ए) (ii) पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि इस तरह के संयंत्र में उत्पन्न कुल बिजली का कम से कम 51 प्रतिशत वार्षिक आधार पर कैप्टिव उपयोग के लिए निर्धारित किया जाता है।नियम धारा 2 (8) की आवश्यकता के अनुरूप है कि मुख्य रूप से बिजली अपने स्वयं के उपयोग/सदस्यों के लिए कैप्टिव उत्पादन संयंत्र द्वारा उत्पन्न की जानी चाहिए।2005 के नियमों के नियम 3 (1) (ए) (ii) के प्रावधानों को अधिनियम के उद्देश्यों के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है। बल्कि यह अधिनियम में ही निर्धारित प्रावधान और आवश्यक योग्यताओं के औचित्य को बढ़ावा देता है।

इसी तरह, नियमों के नियम 3 (1) (ए) का दूसरा प्रावधान अधिनियम की धारा 2 (8) को आगे बढ़ाने में है।

64. इस प्रकार कंपनियों या निगमित निकायों के एक संघ को नियम 3 (1) (ए) के दूसरे परंतुक के साथ पढ़े गए नियम 3 (1) (ए) का पालन करना आवश्यक है।समान रूप से, कंपनियों, निकाय निगमों या अन्य व्यक्तियों का एक संघ जो एक एस. पी. वी. स्थापित करता है जो सी. जी. पी. का स्वामित्व, रखरखाव और संचालन करता है, उसे नियम 3 (1) (ए) का पालन करना आवश्यक है जिसे नियम 3 (1) (ए) के दूसरे परंतुक के साथ पढ़ा जाता है।इस संबंध में एक एस. पी. वी. कंपनी हो सकती है, लेकिन यह नियम 3 (1) (ए) के दूसरे परंतुक के संदर्भ में व्यक्तियों का एक संघ भी है।

65. हम किसी भी तरह से नियम 3 (1) (बी) को नियमों के नियम 3 (1) (ए) पर अधिस्थापक या प्रचलित नहीं कह सकते। इस तर्क को स्वीकार करना, वास्तव में, यह स्वीकार करना होगा कि "गेमिंग", जैसा कि ऊपर वर्णित है, अनुमत है यदि कोई कंपनी अपने शेयरधारकों या अन्य निकाय निगमों को बिजली पैदा करने और आपूर्ति करने के उद्देश्य से एक एस. पी. वी. के रूप में बनाई गई है। उदाहरण के लिए, एक स्वतंत्र बिजली उत्पादक के रूप में स्थापित एक उत्पादन कंपनी, जो एक संयंत्र में 98 प्रतिशत शेयरों की शेयरधारक है, समूह के कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को 2 प्रतिशत शेयर देकर और उन्हें उत्पन्न बिजली का 98 प्रतिशत उपभोग करने की अनुमति देकर सी. जी. पी. के रूप में चल कर सकती है। संयंत्र में 98 प्रतिशत हिस्सेदारी होने के बावजूद स्वतंत्र बिजली उत्पादक उत्पादित बिजली का केवल 2 प्रतिशत ही उपभोग कर सकता है। यह स्पष्ट रूप से धारा 2 (8) के विपरीत होगा, जो "मुख्य रूप से अपने उपयोग के लिए" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। इस प्रस्तुति को स्वीकार करना उन कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को लाभ देने के उद्देश्य और उद्देश्य के विपरीत भी होगा जो अपना पैसा खर्च करते हैं और सी. जी. पी. स्थापित करने में निवेश करते हैं। किसी ऐसे प्रावधान की व्याख्या करते समय जो अस्पष्ट या बहस योग्य हो, न्यायालय या न्यायनिर्णायक को विधायिका के इरादे को ध्यान में रखना चाहिए और शब्दों को इस तरह से पढ़ना चाहिए कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

किसी व्याख्या को स्वीकार करने के बजाय उद्देश्य और उद्देश्य को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दुरुपयोग या दुरुपयोग होता है।

66. उपरोक्त तर्क को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि एस. पी. वी. जो सी. जी. पी. का स्वामित्व, संचालन और रखरखाव करते हैं, वे नियमों के नियम 3 (1) (ए) के दूसरे परंतुक के संदर्भ में "व्यक्तियों का संघ" हैं। कंपनियों, निगमित निकायों और अन्य व्यक्तियों, जो एक एस. पी. वी. द्वारा स्थापित सी. जी. पी. के शेयरधारक और कैप्टिव उपयोगकर्ता हैं, को नियमों के दूसरे प्रावधान के साथ पढ़े गए नियमों के नियम 3 (1) (ए) का पालन करना आवश्यक है।

67. हम तदनुसार तीनों मुद्दों का जवाब देते हैं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

मुद्दों का जवाब दिया।

दिव्या पांडे